



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY



स. 45]
No. 45]

नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 28, 1987/फाल्गुन 9, 1908
NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 28, 1987/PHALGUNA 9, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as
a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 1987

अधिसूचना

यू.ओ.सं.क्रा. 15(90)-8(डी)/86 :—प्रधान मंत्री
और वित्त मंत्री श्री राजीव गांधी द्वारा 1987-88 का
बजट प्रस्तुत करते हुए दिए गए भाषण को एनडू द्वारा प्रकाशित
किया जाता है :—

भाग क

महोदय,

मैं वर्ष 1987-88 का बजट प्रस्तुत करने के लिए
उपस्थित हुआ हूँ।

2. उनतीस वर्ष पहले देश का बजट प्रस्तुत करते हुए
पंडित जवाहर लाल नेहरू ने इस सदन में कहा था :

“हम जिन परिस्थितियों में रह रहे हैं और हमारे देश
को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उन्हें

देखते हुए हम कोई गतिहीन अथवा आत्मसन्तुष्टिपूर्ण
दृष्टिकोण नहीं अपना सकते अथवा ऐसे बोझ से नहीं
बच सकते जो कुछ गति के साथ प्रगति करने के हमारे
मार्ग में अवरोधभावी हैं.....

हमें, अपने सभी साधनों को संरक्षित करके, उत्पादन
बढ़ाकर तथा उत्तरोत्तर और अधिक समतापूर्ण वितरण
सुनिश्चित करने के लिए कोशिश करके अपने सुनियोजित
विकास के वास्ते अपनी पूरी ताकत से प्रयत्न करना है
और इस प्रकार अपने देश की विशाल जनता के स्तरों
को ऊँचा उठाने का प्रयास करना है।”

आज हम इन्हीं उद्देश्यों का अनुसरण कर रहे हैं।

3. जब हमने कार्यभार सम्भाला था तो हम भाग्यशाही
ये कि हमें इन्दिरा जी से सुदृढ़ अव्यवस्था उत्तराधिकार के
रूप में प्राप्त हुई। 1979-80 की कठिन स्थिति के बाद,
मुद्रास्फीति की दर को तेजी से नीचे ला दिया गया था।
विकास की दर में वृद्धि हुई और आधारभूत ढाँचे को फिर से
मजबूत बनाया गया। हमने इन सफलताओं को बनाए रखा
है और उन क्षेत्रों में सुधार की प्रक्रिया आरंभ की है, जिन

पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता थी। मुझे विश्वास है कि इसे हम काफी सीमा तक प्राप्त कर सके हैं।

4. हमारा प्रधान उद्देश्य गरीबी को दूर करना और एक सुदृढ़, आधुनिक, आत्मनिर्भर और स्वतंत्र अर्थव्यवस्था का निर्माण करना है। इन दो वर्षों में हम ने निर्धनता को दूर करने के लिए पूरे ओर से काम शुरू किया है। पिछले बजट में गरीबी दूर करने के कार्यक्रमों के लिए निर्धारित प्रत्यक्ष परिव्ययों में भारी वृद्धि की गई थी। अगस्त में 20-सूत्री कार्यक्रम (1986) की उद्घोषणा की गई। खाद्य के ऊँचे भण्डारों को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों का और विस्तार किया गया। जनजातीय क्षेत्रों को 20 लाख मीट्रिक टन अनाज अत्यंत रियायती दरों पर मुहैया किया गया। हमने नगरों में बसने वाले गरीब लोगों के लिए रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने के प्रयोजन से एक महत्वपूर्ण योजना शुरू की। मैंने अपने देश के सबसे ज्यादा पिछड़े और दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा किया और वहाँ पर चल रहे कार्यों को देखा। लोगों से प्रत्यक्ष बात करने पर मुझे पता चला है कि अभी कितना काम और ज्यादा करना बाकी है। मुझे विश्वास है कि हम गरीबी को दूर करने के लिए जो कठिन संघर्ष कर रहे हैं उसमें हमें काफी सफलता मिली है।

5. कृषि हमारी अर्थव्यवस्था का आधार है। गरीबी को दूर करने के लिए इस क्षेत्र का विकास अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारे किसानों, कृषि प्रौद्योगिकीविदों और वैज्ञानिकों ने, छाछानों के एक आयातकर्ता और जीवन के सीमान्तिक स्तर पर रह रहे हमारे देश को आत्म-निर्भर बना दिया है। हम उन पर गर्व करते हैं। हम उन्हें बढ़ाई देते हैं।

6. हमने उन नीतियों को और भी मजबूत बनाया है जो इतनी कामयाब साबित हुई हैं। हम अपने किसानों को उनकी उपज के लिए लाभदायक मूल्य दिलवाने और उनके लिए अधिक मात्रा में पानी, बिजली, बीज, उर्वरक और ऋण उपलब्ध कराने के लिए वचनबद्ध हैं। कमजोर मानसून वर्षा के बावजूद अनाज का उत्पादन 15 करोड़ मीट्रिक टन से अधिक होगा। हमने अपने किसानों को और ज्यादा प्रोत्साहन दिए हैं, ताकि चीनी और खाद्य तेलों के आयात पर हमारी निर्भरता कम हो सके। उन्होंने भी बहुत शानदार काम किया है।

7. किन्तु मुझे कृषि क्षेत्र के श्रमिकों के बारे में चिंता है। कृषि श्रमिकों को शोषण का सामना करना पड़ता है। सरकार एक राष्ट्रीय ग्रामीण श्रमिक आयोग की स्थापना करेगी। यह आयोग हमारे समाज के इस कमजोर वर्ग की कामकाज की स्थितियों का अध्ययन करेगा और उनकी सुरक्षा के लिए सामाजिक कानूनों के कार्यान्वयन को भी देखेगा।

8. उद्योग धंधे उन्नति कर रहे हैं। छठी आयोजना में उद्योगों के आधुनिकीकरण और औद्योगिक निवेश के संवर्धन के लिए बड़े उपाय शुरू किए गए थे। सातवीं आयोजना में

हमारी नीति इन्हीं उपायों की नींव के आधार पर औद्योगिक कार्य-निष्पादन में और सुधार करने की है। हम अनुकूल स्तरों पर किए जाने वाले उत्पादन के परिणामस्वरूप प्राप्त होने वाले अधिक लाभ को बढ़ावा देने और आधुनिक प्रौद्योगिकी का समावेश करने तथा उत्पादकता में वृद्धि के लिए पहले से ज्यादा प्रतियोगिता की स्थिति उत्पन्न करने, लागतों में कमी करने और गुणवत्ता में सुधार करने के लिए प्रोत्साहन दे रहे हैं। हमने छोटे पैमाने के एककों को दिए जाने वाले प्रोत्साहनों में वृद्धि की है। अब इस बात के स्पष्ट प्रमाण हैं कि इन नीतियों के अर्थ-व्यवस्था पर प्रत्याशित प्रभाव पड़ रहे हैं।

9. हमारे औद्योगिक आधार का विस्तार हुआ है। नए उद्योग स्थापित हुए हैं। लघु उद्योग क्षेत्र का तेजी से विस्तार हुआ है। बड़ी संख्या में नए रोजगारों का सृजन किया गया है। 1984-85 से आरंभ होने वाले तीन वर्षों में उद्योग धंधों की वृद्धि की दर औसतन प्रति वर्ष आठ प्रतिशत से ज्यादा होने की संभावना है। पिछले 20 वर्षों में इतनी वृद्धि कभी नहीं हुई।

10. हमने कर सुधार के महत्वपूर्ण काम को उच्च प्राथमिकता प्रदान की है। हमारे कर कानून और नियम बहुत जटिल हो गए थे। बड़ी मात्रा में करों की चोरी होती थी। इनमें सुधार अत्यंत आवश्यक था। पिछले दो वर्षों में हमने राजकोषीय प्रणाली में जो सुधार किए हैं वे बहुत ही व्यापक और सफल रहे हैं। हमने कर की दरों और कर संरचना को तर्कसंगत बनाया है। हमने कानूनों और प्रक्रिया को सरल बना दिया है। हमने बिना किसी भय अथवा पक्षपात के इन कानूनों को कठोरता से लागू किया है। इससे ईमानदार करदाता को मदद मिली है, और पहले की अपेक्षा अधिक राजस्व प्राप्त हुआ है।

11. सरकारी क्षेत्र हमारी औद्योगिक अर्थ-व्यवस्था का नेतृत्व है। मुझे यह भी विश्वास है कि हमारे सरकारी क्षेत्र के उद्यम विश्व के किसी भी उद्यम के समान कुशल बन सकते हैं। मुझे यह कहते हुए खुशी है कि सरकारी क्षेत्र के आधारभूत उद्योग स्पष्ट रूप से बेहतर कार्य निष्पादन कर रहे हैं। कोयला, बिजली तथा रेलवे में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। तापीय विद्युत के उत्पादन में जो सुधार हुआ है वह खासतौर पर सराहनीय है। चालू वर्ष में संयंत्र भार अनुपात 1976-77 से लेकर अबतक के अनुपात से सर्वाधिक है। आधारभूत तंत्र के संचालन में जो सुधार आया है, उसे प्रबंध व्यवस्था में परिवर्तन करके और कार्यशाला के वास्तविक कार्य-निष्पादन को बेहतर बनाकर संभव बनाया जा सका है।

12. सरकार, सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कार्यनिष्पादन में और सुधार लाएगी। हम उनकी स्वायत्तता को मजबूत करेंगे तथा उन्हें परिणामों के लिए उत्तरदायी ठहराएंगे। सरकार, सरकारी क्षेत्र के संबंध में संसद के सम्मुख एक प्रवेत-पत्र प्रस्तुत करेगी।

13. एक राष्ट्र के रूप में हम अपनी आर्थिक उपलब्धि से संतुष्ट हो सकते हैं। एक ऐसी अवधि में जबकि अनेक विकासशील देशों में वृद्धि की दरों में तेजी से कमी आई है, हम अपनी विकास दर को तेज करने व प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने में समर्थ रहे हैं। हम श्रृण संबंधी समस्याओं से बचे हैं और हमने मुद्रास्फोति को नियंत्रण में रखा है। हमारे खाद्यान्नों के भण्डार तथा विदेशी मुद्रा को प्रारक्षित निविदां संतोषजनक हैं। इनसे पर्याप्त संबल मिलता है। किन्तु हम इसी से संतुष्ट नहीं हो सकते। विश्व का माहौल, राजनीतिक और आर्थिक दोनों प्रकार का, प्रतिकूल बना हुआ है। कुछ महत्वपूर्ण घरेलू समस्याएं भी हैं जिनपर हमें ध्यान देने की जरूरत है।

14. सरकारी खर्च में तेजी से वृद्धि के कारण हमारे राजकोषीय संतुलन पर भारी दबाव पड़ रहा है। हाल ही में, हमें अपने रक्षा व्यय में वृद्धि करनी पड़ी। राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में हम कोई भी प्रयास बाकी नहीं छोड़ेंगे और न ही किसी भी त्याग से पिछे रहेंगे। इसके साथ ही विकास के लिए दबाव बहुत अधिक है। इस समय किसी भी महत्वपूर्ण निवेश में शिथिलता बरतने से, उसका भविष्य में बुरा प्रभाव पड़ेगा। ऐसे कार्यक्रमों पर खर्च करना, जिनसे गरीबों को सीधे ही लाभ मिलता है, और खाद्यान्नों के लिए आर्थिक सहायता देना एक अनिवार्य सामाजिक आवश्यकता है। वर्तमान वर्ष के दौरान, वेतन आयोग की रिपोर्ट के कार्यान्वयन के फलस्वरूप हमें खर्च संबंधी अतिरिक्त प्रतिबद्धताएं निभानी पड़ी। सूखे भयबा बाढ़ से पीड़ित अनेक राज्यों को अधिक राहत और अनुदान देना भी आवश्यक हो गया।

15. कुछ भी हो, यह स्पष्ट है कि हमें अपने खर्च को साधनों के अन्दर ही सीमित रखने के लिए कुछ कठोर निर्णय लेने होंगे। सरकार ऐसे निर्णय लेने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञा है। हमें अपनी व्यय संबंधी नीति की बारीकी से समीक्षा करने की आवश्यकता है। जहाँ-तहाँ कुछ कटौती करने से काम नहीं चलेगा। इससे पहले के अस्थायी उपायों और यत्न-तत्न कटौतियों के लाभ केवल अस्थायी रहे हैं और उनके टिकाऊ परिणाम प्राप्त नहीं हो सके हैं। व्यर्थ, आढम्बरपूर्ण अथवा अनुत्पादक खर्च की कोई गुंजाइश नहीं है। राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हमें इकट्ठे होकर व अधिक परिश्रम से कार्य करना होगा।

16. मूल्य-व्यवस्था में हमारी अच्छी उपलब्धि रही है। तथापि, मूल्यों की स्थिति के संबंध में अत्यंत निष्क्रिय दृष्टिकोण अपनाना एक गलती होगी। एक विकासशील अर्थ-व्यवस्था में मांग और पूर्ति का सन्तुलन सदा ही नाजुक रहा है। किसी भी बाहरी अथवा आन्तरिक अव्यवस्था से कठिनाइयाँ पैदा हो सकती हैं। इसलिए यह जरूरी है कि मूल्यों की स्थिति पर सावधानीपूर्वक निगरानी रखी जाए।

17. हमारे भुगतान संतुलन पर दबाव बना हुआ है। हमें इसका प्रदाजा था और हमने आयातों में वृद्धि को कम करने तथा निर्यातों को बढ़ाने के लिए बहुत से कदम उठाए

थे। इनके अच्छे परिणाम निकले हैं। चालू वर्ष के पहले 9 महीनों में निर्यातों में 17 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि आयातों में केवल लगभग 2 प्रतिशत की वृद्धि हुई। व्यापार घाटा पिछले वर्ष की तुलना में 1000 करोड़ रुपए कम है। किन्तु काफी और किया जाना बाकी है। यह सुधार अंशतः तेल की कीमतों में गिरावट के कारण है और हम अगले वर्ष इस पर भरोसा नहीं कर सकते। सरकार बाहरी मार्ग पर पूर्णतः सतर्क रहेगी।

18. पिछले दो वर्षों में शुरू की गई नीतियों के परिणामों से पता चलता है कि हमारी विज्ञा सही है। मेरा प्रस्ताव इस वर्ष के बजट में कुछ चुने हुए क्षेत्रों में एक नया मोड़ देने का है जिनसे अर्थ-व्यवस्था को मजबूती मिलेगी और हमारे सातवीं आयोजना के उद्देश्यों को बढ़ावा मिलेगा। इनमें सर्वप्रथम शिक्षा है।

19. संसद ने नई शिक्षा नीति को व्यापक और विस्तृत चर्चाओं के पश्चात् स्वीकार किया है। इस नीति का प्रतिपादन राष्ट्रीय सम्मति से किया गया है। यह नीति निर्धनता से संघर्ष करने के लिए एक सशक्त साधन है। सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लोगों को इस नीति के माध्यम से अवसरों की समानता की अनुभूति प्राप्त होती है, जिसकी गारंटी हमारे संविधान द्वारा दी गई है। इससे हम अपनी विरासत को सुरक्षित रख सकेंगे तथा अपने देश के युवाओं की रचनात्मक शक्ति को कार्यरूप में परिणत कर सकेंगे। यह विभिन्न भाषा बोलने वाले लोगों, अलग-अलग धर्मों को मानने वाले और अलग-अलग सांस्कृतिक परम्पराओं से जुड़े लोगों को, जोकि भारत की मिली-जुली संस्कृति का ही अंग है, एक सूत्र से पिरोएंगी। सभी क्षेत्रों में, अर्थात् विज्ञान, शैक्षणिकी, कला, मानविकी तथा दार्शनिक सिद्धांतों के क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करना ही इस नीति का उद्देश्य है।

20. नई नीति को एक अच्छी शुरुआत प्रदान करने के लिए मैंने शिक्षा के लिए 800 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं जबकि इसकी तुलना में 1986-87 में 352 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। यह विशाल वृद्धि, देश में शैक्षिक तबदीली लाने के हमारे संकल्प की दिशा में एक कदम है।

21. प्रमुख रूप से राज्य सरकारों शिक्षा के लिए उत्तरदायी हैं। इन संसाधनों से राज्य सरकारों के प्रयासों को समर्थन प्राप्त होगा।

22. गरीबी दूर करने के कार्यक्रमों की गति को बनाए रखा जाएगा। वर्ष 1985-86 में, राज्यों को, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम का विस्तार करने के लिए दस लाख मी. टन खाद्यान्न अनुदान स्वरूप दिए गए जिसके फलस्वरूप 620 लाख मानव दिवसों का अतिरिक्त रोजगार पैदा हुआ। वर्ष 1986-87 में खाद्यान्नों का अतिरिक्त आवंटन बढ़ाकर बीस लाख मी. टन कर दिया गया जिससे 1280 लाख मानव दिवसों

का अतिरिक्त रोजगार पैदा हुआ। मेरा प्रस्ताव रोजगार के लिए अतिरिक्त खाद्यान्न आवंटित करने के कार्यक्रम को जारी रखने का है।

23. एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम को और सुदृढ़ किया जाएगा। इस वर्ष के दौरान 32 लाख से अधिक परिवारों को इससे लाभ पहुंचने की आशा है। आगामी वर्ष के दौरान 310 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की जा रही है। राज्यों के अनुपातिक आवंटनों और बैंकिंग क्षेत्र के उधारों को मिलाकर इस कार्यक्रम के अन्तर्गत निधियों का कुल प्रवाह इस आवंटन की तुलना में 4 से 5 गुना तक अधिक होगा। 1987-88 में ग्रामीण विकास विभाग के लिए कुल आयोजनागत परिव्यय 2,000 करोड़ रुपए से अधिक होगा। यह लगभग 3,600 करोड़ रुपए के छोटी आयोजना के कुल व्यय के तुलनीय है।

24. आवासन यानी मकानों के निर्माण के कार्य को हमें सर्वोच्च प्राथमिकता देनी है। यह एक बुनियादी जरूरत है। इससे रोजगार भी पैदा होता है। हम, मकान बनाने के एक व्यापक कार्यक्रम का, विशेष रूप से आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लोगों के लिए आवास बनाने के कार्यक्रम का प्रस्ताव रखते हैं।

25. केन्द्रीय सरकार ने इन्दिरा आवास योजना के लिए 1987-88 में फिर 125 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की है। इस योजना के अन्तर्गत सातवीं आयोजना की अवधि में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए 10 लाख मकान बनाए जाएंगे। हमने फंसला किया है कि राज्य सरकारों को यह छूट होगी कि वे इस कार्यक्रम के तहत उन्हें आवंटित राशि का उपयोग, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए मकानों के वास्ते ऋणों के लिए इन्दिरा आवास योजना सोसाइटियां स्थापित करने के लिए सीड पूंजी के रूप में कर सकती है।

26. आवासन के लिए निधियों की व्यवस्था करने के वास्ते एक नई वित्तीय व्यवस्था का निर्माण किया जाएगा। शीर्ष स्तर पर, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 100 करोड़ रुपए की इक्विटी पूंजी के साथ एक नए राष्ट्रीय आवासन बैंक की स्थापना की जाएगी। यह बैंक, स्थानीय तथा क्षेत्रीय, दोनों ही स्तरों पर, आवासन संस्थाओं का प्रवर्तन करेगा। ब्यौरों के संबंध में रिजर्व बैंक अलग से घोषणा करेगा।

27. राष्ट्रीय शहरीकरण आयोग ने, अपनी अन्तरिम रिपोर्ट में आवास से संबंधित कानूनों में, जिनमें शहरी भूमि (सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 भी शामिल है, अनेक परिवर्तन करने का सुझाव दिया है। इस महत्वपूर्ण सामाजिक कानून का उद्देश्य, शहरी क्षेत्रों में अधिशेष भूमि का सार्वजनिक हित के लिए उपयोग करना था। किन्तु प्राप्त परिणाम निराशाजनक रहे हैं। यद्यपि 10 वर्ष बीत गए हैं किन्तु अधिशेष अधिष्ठित की गई भूमि के एक प्रतिशत के आधे से भी कम भाग को ही बस्तुतः निर्माण के लिए उपयोग

में लाया गया है। इसी बीच, भूमि की कमी के कारण, शहरी क्षेत्रों में किरायों में और सट्टेबाजी के लाभों में बहुत वृद्धि हुई है। इसका गरीबों पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है। इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। मैंने, शहरी विकास मंत्रालय से कहा है कि वह आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त विधायी प्रस्ताव तैयार करे और उन्हें सदन के सम्मुख विचारार्थ प्रस्तुत करें।

28. आयोग ने किराया नियंत्रण अधिनियमों में कतिपय परिवर्तन किए जाने की सिफारिशों भी की हैं, जिनसे आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लोगों को सुरक्षा प्रदान करने के साथ-साथ नए मकानों के निर्माण के लिए पर्याप्त प्रोत्साहनों की व्यवस्था हो सकेगी। इन परिवर्तनों से कुछ अरसे में मकानों की उपलब्धता में सुधार होने से किराए भी कम हो जाएंगे। आयोग की इस रिपोर्ट को राज्य सरकारों के पास कार्यान्वयन के लिए भेजा जाएगा।

29. बाद में अपने भाषण में, मैं आयकर दाताओं के लिए उनके द्वारा विनिर्दिष्ट संस्थाओं से लिए गए आवास ऋणों के संबंध में कुछ रियायतों की घोषणा करूंगा।

30. पिछले दो वर्षों के दौरान, सरकार ने श्रमिकों के कल्याण के लिए अनेक कदम उठाए हैं। इनमें, श्रमिकों को देय राशि के संरक्षण के लिए कानून संबंधी परिवर्तन, श्रमिकों के लिए नई स्टॉक आस्थान स्कीम प्रारम्भ करना, बीनस अदायगी के लिए पात्रता सीमा में वृद्धि, सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते की दर में वृद्धि, श्रमिकों के लिए मकानों में निवेश करने के लिए कर संबंधी रियायत, श्रमिक भविष्य निधियों पर दिए जाने वाले ब्याज की दर में वृद्धि और आयकर से छूट के लिए मकान किराया भत्ते की सीमा को समाप्त करना शामिल है। और उपाय के रूप में आय-कर अधिनियम में कुछ कानून संबंधी परिवर्तन करने का प्रस्ताव है ताकि भविष्य निधि, ई.एस.आई. और उपादन के रूप में श्रमिकों को प्राप्त होने वाली राशि को संरक्षण प्रदान किया जा सके।

31. छोटी बचतें जुटाने में हमने उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। सरकार द्वारा पिछले वर्ष गठित विशेषज्ञ दल ने वैयक्तिक बचतों संबंधी कर प्रोत्साहनों की वर्तमान योजना में कतिपय कठिनाइयों का उल्लेख किया है। एक महत्वपूर्ण कमी यह है कि आजकल सकल बचतों के लिए ही राज-कोषीय रियायतें उपलब्ध हैं और बचत न करने के लिए कोई दण्ड नहीं है। इसलिए इसने ऐसे प्रणाली अपनाते की सिफारिश की है जिसमें निवल बचतों को प्रोत्साहन प्राप्त हो।

32. वास्तविक बचत के सिद्धांत के आधार पर मैं एक नई बचत योजना शुरू करने का प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूँ। संक्रमणकालीन समस्याओं से बचने के लिए यह योजना फिलहाल राष्ट्रीय बचत पत्रों तथा बचत के अन्य माध्यमों के संबंध में आय-कर अधिनियम की धारा 80ग के अन्तर्गत उपलब्ध कर राहतों के अतिरिक्त होगी। इस नई योजना के

अन्तर्गत जमा राशि के 50 प्रतिशत हिस्से पर अधिकतम 20,000 रुपए तक, आय-कर संबंधी कटौती मिलेगी। किन्तु जिस वर्ष इस रकम की निकासी की जाएगी, उस वर्ष ली जाने वाली राशि के 50 प्रतिशत भाग को कराधान योग्य आय में जोड़ दिया जाएगा। इस योजना के अन्तर्गत होने वाली प्राप्तियों का वंटवारा राज्यों के साथ भी किया जाएगा। इस नई बचत योजना का पूरा व्यौरा, जिसे अगले वित्तीय वर्ष में प्रारंभ किया जाएगा, अलग से घोषित किया जाएगा।

33. भारत में पूंजी बाजारों में पिछले कुछ वर्षों में अग्रा वृद्धि हुई है। वर्ष 1986-87 में पूंजी निर्गमों के लिए दी गई अनुमतियां 5000 करोड़ रुपए से अधिक हो गई हैं। जबकि यह 1980-81 में लगभग 500 करोड़ रुपए थी। पूंजी बाजारों के स्वस्थ विकास के लिए यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि निवेशकर्ता के अधिकारों को पूर्णतः संरक्षण प्रदान किया जाए और व्यापारिक कुप्रथाओं को रोक दिया जाए। सरकार ने, पूंजी बाजारों के स्वस्थ विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से स्थाक एक्सचेंजों और प्रतिभूति उद्योग के विनियमन और नियमित कार्यचालन के लिए एक अलग बोर्ड गठित करने का निर्णय किया है।

34. पिछले वर्ष भारतीय यूनिट ट्रस्ट ने छोटे निवेश-कर्ताओं को आकर्षित करने के लिए सामान्य ग्रेडों में निवेश करने के प्रयोजन से एक सांझी निधि की स्थापना की थी। निवेशकर्ताओं को चयन के लिए एक विस्तृत क्षेत्र उपलब्ध कराने की दृष्टि से भारतीय स्टेट बैंक भी एक ऐसी ही सांझी निधि की स्थापना करेगा। मैं भी बाद में कुछेक उपायों की घोषणा करूंगा जिनसे पूंजी बाजारों के विकास में योगदान मिलेगा।

35. मैंने औद्योगिक विकास की गति में तेजी लाने की बात कही है। सरकार का मुख्य प्रयास भारत के औद्योगिक ढांचे को आधुनिक बनाना है। कार्यकुशलता और उत्पादकता दोनों में ही वृद्धि की जानी है। मौजूदा प्रौद्योगिकी का स्तर भी बढ़ाया जाना है। नई प्रौद्योगिकी को अपनाया जाना है और उसका स्वदेश में ही और विकास किया जाना चाहिए। लागतों को कम करना भी बहुत जरूरी है। ये सभी उद्देश्य एक मध्यावधिक ढांचे के आधार पर ही सफलतापूर्वक पूरे किए जा सकते हैं।

36. सरकार अलग-अलग उद्योगों की गहराई से समीक्षा कर रही है। अनेक महत्वपूर्ण उद्योगों, जैसे कि वस्त्रोद्योग, जूट, चीनी, ओषध, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा साफ्टवेयर के संबंध में नई नीतियां घोषित की गई हैं। हमने वस्त्रोद्योग आधुनिकीकरण निधि और जूट आधुनिकीकरण निधि की भी स्थापना की है। इससे इन पारम्परिक उद्योगों के आधुनिकीकरण में सुविधा होगी, जो पर्याप्त संख्या में लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं। जूट उद्योग के लिए एक अन्य विशेष विकास निधि की स्थापना की जा रही है। इससे उत्पादकों और श्रमिकों, विविधीकरण, अनुसंधान और विकास को लाभ पहुंचेगा।

37. सरकार चुने हुए उद्योगों के संबंध में समग्र नीति विषयक मंरचना की व्यवस्थित ढंग से समीक्षा जारी रखेगी और विकास व आधुनिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी।

38. आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के हमारे प्रयासों में पूंजीगत वस्तु उद्योग की भूमिका महत्वपूर्ण है। इस उद्योग की प्रगति में और तेजी लाने के उद्देश्य से मेरा प्रस्ताव उपायों का एक पैकेज लागू करने का है। प्रथमतः मशीनों के लिए, जिनमें सामान्य परियोजना आयात शामिल है, आयात शुल्क की दरों को सहायोजित किया जा रहा है। दूसरे, कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों, जैसे कि विद्युत, भारी उपस्कर और वस्त्रोद्योग, मशीनरी के स्वदेशी विनिर्माण की लागत को कम करने के उद्देश्य से, कुछ प्रकार के आयातित इस्पात की लागत कम की जा रही है। इन प्रस्तावों के बारे में, मैं बाद में कुछ कहूंगा।

39. तीसरे, चुने हुए पूंजीगत वस्तु उद्योगों में प्रौद्योगिकी उन्नयन का एक विशेष कार्यक्रम, वित्तीय संस्थाओं द्वारा इस योजना के अंत तक की तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रारंभ किया जाएगा। इसके अन्तर्गत प्रारंभ में बिजली की मशीनरी, जिसमें विद्युत उपस्कर तथा बिजली की मोटरें शामिल हैं, फाउंड्रीज तथा मशीनरी पुर्जे शामिल होंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य इन क्षेत्रों में आधुनिकतम प्रौद्योगिकी लागू करना, निरन्तर उन्नयन के लिए स्वदेशी अनुसंधान और विकास सुविधाओं में सुधार करना तथा लागतों में कमी लाना है। न्यौरे, अलग से, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा घोषित किए जाएंगे।

40. हमारे विकास में कृषि से सम्बद्ध उद्योगों की एक विशेष भूमिका है। इनसे कृषि उत्पादों के लिए बाजार उपलब्ध होता है और हमारे किसानों की आमदनी में वृद्धि होती है। मैंने, कृषि-आधारित दो सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योगों, यथा जूट और वस्त्र, के आधुनिकीकरण के लिए किए गए उपायों का पहले ही उल्लेख किया है। पिछले वर्ष के बजट में, बनस्पति में कुछ स्वदेशी तेलों, जैसे कि चावल की भूसी का तेल, महुआ तेल और बिनोले का तेल आदि का उपयोग करने के लिए महत्वपूर्ण कर संबंधी प्रोत्साहनों की घोषणा की गई थी। अपने भाषण में, मैं कुछ प्रस्तावों की घोषणा करूंगा। मेरा प्रस्ताव खाद्य संसाधन उद्योगों के विकास को भी प्रोत्साहित करने का है, जिनसे किसानों और उपभोक्ताओं को लाभ होगा। कुछ अन्य प्रस्ताव हैं जिनसे कपास और ऊन को लाभ होगा।

41. पिछले वर्ष, सरकार ने निर्यात प्रधान उद्योगों के समर्थन के लिए अनेक उपाय किए थे। नकद प्रतिपूर्ति समर्थन और सीमा-शुल्क वापसी की नई योजनाएं प्रारंभ की गई हैं। चुने हुए निर्यात उद्योगों के लिए पूंजी उपस्कर पर आयात शुल्क में कटौती कर दी गई है। ब्याज की दरों को कम कर दिया गया है। अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों पर विनिर्दिष्ट कच्चे माल की व्यवस्था की जा रही है। राजकोषीय प्रोत्साहन भी प्रदान किए गए हैं। निर्यातों में अब वृद्धि हो रही है। इस बजट में मैं निर्यात उत्पादन में वृद्धि करने के संबंध में कुछ और उपायों का प्रस्ताव करूंगा।

42. माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे आशा है कि इन प्रस्तावों तथा अन्य बजट प्रस्तावों से हमारे समाज की उत्पादक शक्तियों को ताकत मिलेगी। सातवीं आयोजना, वस्तुतः हमारी सभी पंचवर्षीय आयोजनाओं की मूलभूत धारणा यह है कि विकास तथा वृद्धि, गरीबी को दूर करने के वास्तविक उपाय हैं। गरीबी को दूर करने के लिए हमारे समाज में सीधे उपाय करना अपरिहार्य है। तथापि, ऐसे उपायों को तीव्रविकास से ही संबल मिल सकता है। पं० जवाहरलाल नेहरू ने इस सदन में दूसरी पंचवर्षीय आयोजना प्रस्तुत करते हुए हमें यह संदेश दिया था :

“इसलिए हमें समानता पर और, असमानताओं को दूर करने पर अधिक जोर देना है और सदा यह याद रखना है कि समाजवाद का अर्थ गरीबी को बांटना नहीं है। असली बात यह है कि सम्पत्ति और उत्पादन में वृद्धि होनी चाहिए...”

43. हम केवल तभी तेजी से प्रगति कर सकते हैं जबकि हम आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करें। बेरोजगारी और गरीबी की समस्याओं से निपटने का यही एक प्रभावी तरीका है। जो बुद्धिमान व्यक्ति सामाजिक न्याय के नाम में आधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग की आलोचना करते हैं उन्हें पंडित जी के शब्दों पर ध्यान देना चाहिए, जिन्होंने अपने उसी भाषण में कहा था :

“यह नहीं समझिए कि प्रौद्योगिकीय प्रगति के बिना हम बेरोजगारी की समस्या का समाधान कर लेंगे..... यदि भारत को प्रगति करनी है, तो भारत को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रगति करनी चाहिए और भारत को नवीनतम तकनीकों का उपयोग करना चाहिए, सदा इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए कि निःसन्देह, ऐसा करने में, बीच की अवधि के दौरान, जो सदा आती है, दुःख अथवा कठिनाई पैदा नहीं होनी चाहिए।”

44. तो यह है हमारी बुनियादी कार्य-नीति, अर्थात् निरंतर विकास का एक ऐसा ढांचा, जो भारतीय कृषि और उद्योग के त्वरित आधुनिकीकरण पर आधारित हो। मैं भारत में समाजवाद के लिए आयोजन करने के प्रति वचनबद्ध हूँ, उस समाजवाद के प्रति, जो हमारी प्रकृति के अनुरूप हो, लेकिन जो एक ऐसा समाजवाद हो, जिसका बुनियादी अर्थ असमानताओं को दूर करना और समान अवसर उपलब्ध कराना है। यह है वह पैमाना, जिसके अनुसार मैं सभी नीतियों और कार्यक्रमों का मूल्यांकन करना चाहता हूँ।

45. अब मैं 1986-87 के संशोधित अनुमानों और 1987-88 के बजट अनुमानों का उल्लेख करूंगा।

संशोधित अनुमान, 1986-87

46. 1986-87 के बजट अनुमानों में कुल 52,883 करोड़ रुपये के खर्च की व्यवस्था थी। बजट के बाद की अनेक घटनाओं के कारण वर्तमान वर्ष में खर्च मूल रूप में अनुमानित खर्च से 7,445 करोड़ रुपये अधिक होने की संभावना है।

47. मैं व्यौरे बताकर सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहता क्योंकि इनका विवरण बजट दस्तावेजों में दिया गया है। मैं केवल कुछेक प्रमुख मदों का जिक्र करूंगा।

48. आयोजना-बिम्ब व्यय में, चतुर्थ वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप होने वाले खर्च सहित, 5,508 करोड़ रुपये की वृद्धि होने की संभावना है। बफर स्टॉक रखने की लागत को कम करने के लिए भारतीय खाद्य निगम को नरम शर्तों पर, 1,200 करोड़ रुपये के ऋण दिए जा रहे हैं। ये इसके बराबर के बैंक-वित्त का स्थान लेंगे। विभिन्न कारणों से, जिनकी जानकारी सदन को है, हमने रक्षा व्यय में 1,466 करोड़ रुपये की वृद्धि की है। ग्याज संबंधी अदायगियां 800 करोड़ रुपये अधिक होंगी।

49. आयोजना खर्च मूल अनुमानों से 1,937 करोड़ रुपये अधिक होने की संभावना है। केन्द्रीय आयोजना के लिए बजटीय समर्थन 13,617 करोड़ रुपये से बढ़कर 14,792 करोड़ रुपये हो जाने की संभावना है। 1,175 करोड़ रुपये की वृद्धि मुख्यतः दूर संचार, रेलवे, पेट्रोलियम, खान, वस्त्रोद्योग और परमाणु ऊर्जा क्षेत्रों पर है। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की आयोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता 762 करोड़ रुपये अधिक होगी जिसका मुख्य कारण प्राकृतिक आपदाओं से ग्रस्त राज्यों को 510 करोड़ रुपये की अतिरिक्त अभ्रम आयोजना सहायता दिया जाना है। आयोजना और आयोजना-बिम्ब, दोनों को मिलाकर, राज्यों को प्राकृतिक आपदाओं के लिए सहायता, 150 करोड़ रुपये के बजट अनुमानों की तुलना में 640 करोड़ रुपये अधिक होगी।

50. जहाँ तक प्राप्तियों का संबंध है, निवल कर राजस्व, 22643 करोड़ रुपये के बजट अनुमानों की तुलना में 1,564 करोड़ रुपये अधिक होने का अनुमान है। यह एक बड़ी वृद्धि है जो हमारे कर-कानूनों को कठोरता से लागू करने से संभव हुई है। कर-बिम्ब राजस्व तथा पूंजीगत प्राप्तियां, जिनमें तेल क्षेत्र का अंशदान शामिल है, 27,836 करोड़ रुपये होने का अनुमान है जबकि बजट अनुमान 26,537 करोड़ रुपये था। कुल प्राप्तियां 52,043 करोड़ रुपये होंगी तथा कुल खर्च 60,328 करोड़ रुपये होगा। बफर स्टॉक के लिए बैंक क्रेडिट के स्थान पर 1,200 करोड़ रुपये के सरकारी ऋणों सहित, वर्तमान वर्ष में 8,285 करोड़ रुपये का बजटीय घाटा होने का अनुमान है।

51. यह घाटा काफी अधिक है, और मैं इसे ध्यान नहीं समझता। मैंने फैसला किया है कि 1987-88 के बजट अनुमानों में घाटे को बढ़ने नहीं दिया जाएगा। कुछ पूरक मांगें अपरिहार्य होती हैं। मैं मंत्रालयों और केन्द्रीय सरकार के अन्य संगठनों को यह सुनिश्चित करने के अनुरोध दे रहा हूँ कि अतिरिक्त मांगों को समतुल्य बचत करके अथवा अधिक साधन जुटाने के उपायों द्वारा प्रतिसंतुलित किया जाए। हम सरकारी क्षेत्र के एककों के वित्तीय कार्य-निष्पादन की समीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए करेंगे कि आन्तरिक साधन निर्माण

के लक्ष्य प्राप्त किए जाएं। मैं इन उपायों के क्रियान्वयन को मानीटर करने के लिए मंत्रिमंडल की व्यवस्था संबंधी समिति का गठन कर रहा हूँ।

52. कुल मिलाकर, आर्थिक स्थिति अच्छी है और खाद्यान्नों के भंडारों और विदेशी मुद्रा भंडार की स्थिति काफी संतोषजनक है। हम विवेकपूर्ण मांग और पूर्ति प्रबंध के जरिए कीमतों सम्बन्धी समूची स्थिति को काबू में रखने में सफल रहे हैं। व्यवस्था पर नियंत्रण रखने के साथ-साथ, हम अतिरिक्त नकदी को घटाने और संदेवनीय वस्तुओं, विशेषरूप से खाद्यान्नों, चीनी और खाद्य तेलों की सप्लाई में वृद्धि करने के लिए पहले से ही कदम उठाते रहे हैं।

53. मौद्रिक प्रणाली के कार्यक्रम संबंधी समिति की रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक के साथ सलाह करके यह फैसला किया गया है कि अब से आगे बजट दस्तावेजों में बजटीय घाटा और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा केन्द्रीय सरकार को दिए गए ऋणों में हुआ निवल परिवर्तन दिखाया जाए। उक्तोक्त से सरकार के राजकोषीय क्रियाकलापों के मौद्रिक प्रभाव को आंकने का अधिक सही मापदंड सामने आता है। मौजूदा जानकारी के अनुसार, अनुमान है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा केन्द्रीय सरकार को दिए गए निवल ऋण में 1986-87 में 7,250 करोड़ रुपए का परिवर्तन होगा, जो बजटीय घाटे से कम है।

1987-88 के बजट अनुमान

54. मौजूदा स्थिति में, मैंने 1987-88 में आयोजना की गति को बरकरार रखने और हमारी सीमाओं की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। मैंने 1987-88 की केन्द्रीय आयोजना के लिए 24,622 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की है, जिसमें से 14,923 करोड़ रुपए की व्यवस्था बजटीय समर्थन के रूप में की जाएगी। इतने परिव्यय से, हम आयोजना के पहले तीन वर्षों में सातवीं आयोजना के परिव्यय का लगभग 63 प्रतिशत पूरा कर लेंगे। यह एक रिकार्ड है।

55. लेकिन हमें अब और भी अधिक प्रयत्न करने है ताकि हमारे द्वारा निवेश किए गए प्रत्येक रुपए से अपेक्षाकृत अधिक लाभ प्राप्त हो। भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति मात्र धन खर्च करने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। यह जरूरी है कि सरकार कृषिगत करे। हमारे कार्यक्रमों की लागत में कमी किए जाने की आवश्यकता है।

56. इसलिए सरकार ने परियोजनाओं को समय पर क्रियान्वित करने, परियोजनाओं की लागत और उनके पूरा होने के समय को बढ़ने से रोकने, और नए तरीकों तथा नई प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल को उच्च प्राथमिकता दी है। क्रियान्वित की जा रही परियोजनाओं के संबंध में एक मानीटरिंग प्रणाली की स्थापना की गई है।

57. योजनाओं के क्रियान्वयन की मानीटरिंग करना एक अन्य क्षेत्र है, जिसकी ओर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। लेखा शीर्षों और आयोजना के प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल में लाए जाने वाले विकासशीलों के बीच परस्पर समन्वयता लाने के उद्देश्य से, भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के साथ सलाह करते हुए, 1-4-1987 से संशोधित लेखापालन संबंधी वर्गीकरण लागू किया जा रहा है। इससे आयोजना की प्रक्रिया सुदृढ़ होगी और बेहतर मानीटरिंग करने में सहायता मिलेगी। कार्यक्रमों के क्रियान्वयन और उनसे प्राप्त होने वाले लाभों के सम्बन्ध में आधारभूत स्तरों से समय पर पृष्ठ-जानकारी (फीडबैक) प्राप्त करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।

58. केन्द्रीय आयोजना में उन कार्यक्रमों को ऊँची प्राथमिकता प्रदान की गई है, जिनसे ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी को कम करने में सहायता मिलती है। जैसाकि मैंने पहले बताया है, शिक्षा, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम, ग्रामीण जल पूर्ति और और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अतिरिक्त अवसर उत्पन्न करने के लिए खाद्यान्नों के भंडार का इस्तेमाल करने पर विशेष जोर दिया गया है।

59. गरीबी को कम करने में कृषि विकास की बड़ी प्रमुख भूमिका है। केन्द्रीय आयोजना में, कृषि के क्षेत्र में अधिक उपज वाली और उन्नत किस्मों के बीजों की बुवाई के क्षेत्र में वृद्धि करके उत्पादकता बढ़ाने, नई प्रौद्योगिकी का तेजी से अन्तर्गण करने, फसलों की गहनता बढ़ाने, फसल पद्धति में विविधता लाने और हानिकारकों और रोगों का नियंत्रण करने पर पहले की तरह अधिक जोर दिया गया है। इस समय क्रियान्वित किए जा रहे कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं, विशेष चावल उत्पादन कार्यक्रम, राष्ट्रीय तेलहन परियोजना, राष्ट्रीय जल विभाजक क्षेत्र विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय दाल विकास परियोजना। ये परियोजनाएं विशिष्ट कृषि समस्याओं को हल करने के लिए तैयार की गई हैं और इनका हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत प्रभाव पड़ रहा है।

60. कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए कार्यक्रमों में सिंचाई और उर्वरक दो प्रमुख घटक हैं। सिंचाई के क्षेत्र में, निर्माण-धीन परियोजनाओं को पूरा करने पर और सिंचाई-क्षमता तथा उसके उपयोग के बीच के अन्तर को कम करने को उच्च प्राथमिकता दी जा रही है। चालू वर्ष में उर्वरकों का उत्पादन बढ़ कर लगभग 70 लाख मीट्रिक टन हो जाएगा, जबकि पिछले वर्ष लगभग 57 लाख मीट्रिक टन उर्वरकों का उत्पादन हुआ था। पारादीप में स्थित उर्वरक कारखाने में चालू वर्ष के दौरान उत्पादन शुरू हो गया है। अगले वर्ष विजयपुर और आंध्र के उर्वरक कारखानों के, जिनमें से प्रत्येक की क्षमता 72 लाख मीट्रिक टन यूरिया की है, चालू हो जाने की संभावना है।

61. जहाँ तक वित्तीय परिदृश्य का सम्बन्ध है, कुल केन्द्रीय आयोजना में बुनियादी ढाँचे के क्षेत्रों, अर्थात् ऊर्जा, परिवहन और संचार का हिस्सा 54 प्रतिशत से अधिक होगा। 1987-88 में, केन्द्र और राज्यों को मिलाकर, हम 4,880 मेगावाट की अतिरिक्त विद्युत् क्षमता का निर्माण कर लेंगे। जहाँ तक कोयले का सम्बन्ध है, प्रति श्रमिक-पारी (मैन-शिफ्ट) के उत्पादन में 11 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 1987-88 में 18.35 करोड़ मीट्रिक टन कोयले के उत्पादन का लक्ष्य है, जबकि 1985-86 में 16.5 करोड़ मीट्रिक टन का उत्पादन हुआ था।

62. छठी आयोजना की अवधि में, हमें अपने कूड़ तेल के उत्पादन को बढ़ाकर लगभग तिगुना करने में सफलता मिली थी। चालू आयोजना के दौरान उत्पादन में अपेक्षाकृत धीमी गति से वृद्धि होने की संभावना है और नए तेल क्षेत्रों की खोज करने और उनके विकास के लिए निवेश में वृद्धि करना जरूरी है। अगले वर्ष समूचे पेट्रोलियम क्षेत्र के लिए कुल 3,265 करोड़ रुपये का परिदृश्य रखा गया है।

63. सदन का अधिक समय न लेने के उद्देश्य से मैंने 1987-88 की केन्द्रीय आयोजना की केवल कुछ ही प्रमुख उपलब्धियों का उल्लेख किया है। महिला और बाल विकास, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, युवा कार्य और खेल, कला और संस्कृति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, सामाजिक वानिकी और सूचना और प्रसारण जैसे कई अन्य क्षेत्रों में सरकार ने कई नए कार्यों का सूत्रपात किया है, ताकि आयोजना को हमारी जनता के लिए अधिक सार्थक बनाया जा सके। इन कार्यक्रमों को मुदू बनाया जा रहा है। औद्योगिक परियोजनाओं के लिए भी, जिनमें भारी औद्योगिक परियोजनाएं भी शामिल हैं, आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं।

64. मैंने सदन को यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि वर्ष 1987-88 के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का कुल आयोजना परिदृश्य 19,537 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है, जो चालू वर्ष के परिदृश्य से 17 प्रतिशत अधिक है। हमने अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम की आवश्यकताओं का भी ध्यान रखा है, जिन्हें राज्य का दर्जा प्राप्त हो गया है। अगले वर्ष राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की आयोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता देने के लिए 8,754 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है, जबकि इसकी तुलना में चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों में 8,140 करोड़ रुपये की व्यवस्था है।

65. 1987-88 में रक्षा व्यय के बजट अनुमान 12,512 करोड़ रुपये के है। इससे हमारे बजटीय साधनों पर स्वाभाविक रूप से काफी बोझ पड़ा है, लेकिन सदन मुझसे सहमत होगा कि जहाँ तक देश की रक्षा का संबंध है, इस बारे में कोई जोखिम नहीं उठाया जा सकता। हमारी सशस्त्र सेनाओं की शक्ति और मनोबल बहुत ऊँचा है। इस सदन की ओर से मैं अपने जवानों को समूचे राष्ट्र के सम्पूर्ण समर्थन का आश्वासन देता हूँ।

66. अगले वर्ष व्याज की प्रदायगियों की राशि, चालू वर्ष के 9,550 करोड़ रुपये की तुलना में, 10,650 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। खाद्य और उर्वरक संबंधी आर्थिक सहायताओं की राशि के, जिसमें बकाया आर्थिक सहायता भी शामिल है, 3,910 करोड़ रुपये होने का अनुमान है, जबकि चालू वर्ष में यह राशि 3,893 करोड़ रुपये थी। अगले वर्ष के बजट में सरकारी कर्मचारियों को दिए जाने वाले अतिरिक्त महंगाई भत्ते में होने वाली सम्भावित वृद्धि और चौथे वेतन आयोग की सिफारिशों के कारण पेंशन-प्रभारों में होने वाली वृद्धि को पूरा करने के लिए 500 करोड़ रुपये की एक-मुश्त व्यवस्था शामिल है। सरकार ने, जो पेंशनभोगियों की कठिनाइयों के प्रति हमेशा संवेदनशील रही है, न्यूनतम पेंशन और परिवार पेंशन को बढ़ाकर 375 रुपये मासिक करने का फैसला किया है। इससे लगभग 6 लाख पेंशनभोगियों को लाभ पहुंचेगा।

67. 1987-88 में कुल आयोजना-भित्त व्यय 39,266 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। अनुमान है कि अगले वर्ष राज्यों के हिस्से को घटाने के बाद 25,689 करोड़ रुपये का कर-राजस्व प्राप्त होगा, जबकि चालू वर्ष में 24,207 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है। कर-भित्त राजस्व और पूंजीगत प्राप्ति, चालू वर्ष के 27,836 करोड़ रुपये की तुलना में 31,243 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। इस प्रकार, कराधान की मौजूदा दरों पर कुल 56,932 करोड़ रुपये की प्राप्ति होगी, जबकि कुल व्यय 62,942 करोड़ रुपये का होगा, जिससे 6,010 करोड़ रुपये का घाटा रहेगा।

68. अब मैं अपने कर प्रस्तावों की ओर आता हूँ।

भाग ख

69. वर्ष 1985-86 के बजट में हमने करों में व्यापक सुधार की प्रक्रिया शुरू की थी। इस सुधार को स्थूल दिशा और नीति का निरूपण दीर्घकालिक राजकोषीय नीति में किया गया था। इस बजट सत्र में प्रत्यक्ष करों के बारे में हम एक विस्तृत संगोष्ठी विवेक अलग से प्रस्तुत करेंगे। इस विवेक के द्वारा सरलीकरण और युक्तिकरण के उद्देश्य से व्यापक परिवर्तन किए जाएंगे।

70. प्रत्यक्ष करों के सम्बन्ध में मेरे थोड़े से प्रस्तावों का मुख्य जोर बचतों को प्रोत्साहन देने, निवेश को बढ़ावा देने और मकान-निर्माण को समर्थन प्रदान करने पर है। मेरा कुछ कल्याणकारी उपायों का सुदृढ़ बनाने का प्रस्ताव है। मैंने राजस्व में वृद्धि करने के भी कुछ उपायों का प्रस्ताव किया है।

71. मेरा वैयक्तिक और निगम करों के दर-आँध में कोई परिवर्तन करने का प्रस्ताव नहीं है। यह दीर्घकालिक राजकोषीय नीति के अनुरूप है।

72. विदेशी मुद्रा अचाने और राजस्व में वृद्धि करने के उद्देश्य से, मैं विदेश यात्रा के लिए भारत में जारी की गई विदेशी मुद्रा पर 15 प्रतिशत का मामूली-सा कर लगाने का प्रस्ताव करता हूँ। विदेशों में शिक्षा और चिकित्सा-उपचार के लिए जारी की गई विदेशी मुद्रा इसमें शामिल नहीं होगी। यात्राओं पर यह कर अधिशुचित की जाने वाली तारीख से लागू होगा। इस उपाय से 60 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है।

73. जो लोग ऊँची श्रेणी के होटलों में जाने का खर्च उठा सकते हैं, उन्हें राष्ट्रीय खजाने में योगदान करने का अतिरिक्त सुख भी प्रदान किया जाना चाहिए। महंगे होटलों में किए जाने वाले खर्च पर कर लगाने के लिए अलग से एक कानून प्रस्तुत किया जाएगा। 10 प्रतिशत की दर से लगने वाला यह कर विदेशी मुद्रा में की जाने वाली अदायगियों पर लागू नहीं होगा। यह कर अपेक्षित विधान के पारित हो जाने के बाद प्रभावी होगा।

74. मैं निवल बचत पर आधारित एक नई राष्ट्रीय बचत योजना शुरू करने के निर्णय का उल्लेख पहले ही कर चुका हूँ। इस संबंध में आवश्यक वैधानिक परिवर्तन वित्त विधेयक में शामिल किए जा रहे हैं।

75. मैं बच्चों को आवास के क्षेत्र की ओर मोड़ने के लिए राजकोषीय प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव करता हूँ। किसी नई रिहायशी सम्पत्ति की लागत के सम्बन्ध में किसी एक वर्ष के दौरान 10,000 रुपए की सीमा तक ऋणों की वापसी-अदायगी और अदायगी को आय-कर अधिनियम की धारा 80ग के अन्तर्गत जीवन बीमा प्रीमियम अथवा भविष्य निधि में अंशदान के समान कटौती के लिए अर्हता प्राप्त होगी। यह छूट 40,000 रुपए की मौजूदा सीमा के भीतर होगी।

76. किसी रिहायशी मकान की बिक्री से होने वाले पूंजीगत अभिलाभ को छूट दी जाती है, यदि उस अभिलाभ का उपयोग किसी अन्य मकान को प्राप्त करने के लिए किया जाए। अब तक यह बात केवल व्यक्तियों पर लागू होती थी। अब इसे हिन्दू अविभाजित परिवारों पर भी लागू किया जा रहा है।

77. मुझे पता चला है कि मकानों में होने वाली आय पर कर लगाने के प्रयोजन से, हमारे कर-कानूनों में वास्तविक मालिक जो कानूनी मालिक न हों, और कानूनी मालिक, जो वास्तविक मालिक न हों, के बीच भेद किया जाता है। जहाँ तक कराधान का सम्बन्ध है, हम राजस्व सम्बन्धी सुस्थापित परम्पराओं के अनुसरण में, वास्तविक मालिक, जो कानूनी मालिक न हों, और कानूनी मालिक, जो वास्तविक मालिक न हों, दोनों पर कर लगा देने हैं लेकिन किसी मकान मालिक को उपलब्ध रियायतें, केवल उस वास्तविक मालिक को दी जाती हैं, जो कानूनी मालिक भी हों। मैं यह स्पष्ट करके कि वास्तविक मालिक, चाहे यह कानूनी मालिक न भी हों, कर अदा करेगा और कानूनी मालिक

को उपलब्ध होने वाली रियायतें प्राप्त करेगा, कानून को सरल बनाने का प्रस्ताव करता हूँ। मुझे आशा है कि सम्मानित सदस्यों के लिए इस प्रस्ताव का आणव्य पर्याप्त रूप से स्पष्ट होगा।

78. जिन मामलों में किसी सम्पत्ति के अधिग्रहण के लिए मुआवजे की राशि में वृद्धि हो जाती है, अथवा जहाँ नया रिहायशी मकान पुराना मकान बेचने के बाद विनिविष्ट अवधि के अन्दर प्राप्त नहीं किया जाता, वहाँ पहले उद्भूत पूंजीगत अभिलाभ पर कर लगाने के लिए पिछले वर्षों के पूरे हो चुके कर सम्बन्धी मामलों को आशोधित करना पड़ता है। इस जटिलता को दूर करने के लिए कानून में कुछ प्रक्रियात्मक परिवर्तन किए जा रहे हैं।

79. पिछले दो वर्षों में निगम करों के ढाँचे में बहुत से महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं। पहली अप्रैल, 1987 से मूल्यह्रास के उद्धार बनाए गए नियम लागू किए जा रहे हैं। अलग-अलग परिसम्पत्तियों से जुड़ी मौजूदा प्रणाली के स्थान पर, परिसम्पत्तियों के समूह के सम्बन्ध में मूल्यह्रास की अनुमति दी जाएगी। संयंत्र और मशीनरी के लिए मूल्यह्रास की केवल तीन दरें होगी, अर्थात् 100, 50 और 33-1/3 प्रतिशत। इससे न केवल निर्धारण का काम सरल हो जाएगा, बल्कि उद्योग, पूंजीगत उपकरणों का प्रतिस्थापन और आधुनिकीकरण भी अतापूर्वक कर सकेंगे।

80. यह उचित और उपयुक्त ही होगा कि खुशहाल लोग कम से कम कुछ कर अवश्य अदा करें। तथाकथित "शून्य कर" वाली भारी मुनाफा कमाने वाली कम्पनियों के अस्तित्व की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। 1983 में आयकर अधिनियम में एक नई धारा 80फफक शामिल की गई थी, ताकि मुनाफा कमाने वाली सभी कम्पनियाँ कुछ कर अवश्य अदा करें। ऐसा प्रतीत होता है कि इसका कोई लाभ नहीं हुआ और इसे वापस लिया जा रहा है। मैं अब एक उपबन्ध करने का प्रस्ताव करता हूँ, जिसके अनुसार प्रत्येक कम्पनी का आने लेखाओं में घोषित मुनाफे पर एक "न्यूनतम निगम कर" अदा करना होगा। इस नए उपबन्ध के अन्तर्गत, कम्पनियाँ अपनी लेखापुस्तकों में प्रदर्शित मुनाफे के कम से कम 30 प्रतिशत भाग पर कर अदा करेंगी। दूसरे शब्दों में, कोई बहुजन-धारित स्वदेशी कम्पनी अपनी लेखापुस्तकों में दर्ज मुनाफे के कम से कम 15 प्रतिशत के बराबर कर देगी। इस उपाय से लगभग 75 करोड़ रुपए की राजस्व-प्राप्ति होगी।

81. पूंजी बाजारों में उल्लेखनीय उरफुल्लता दिखाई दी है। मेरा कर-कानूनों में कुछ परिवर्तन करने का प्रस्ताव है, जिनसे पूंजी बाजारों के स्वस्थ विकास में सहायता मिलेगी। कुछ श्रेणियों की नई कम्पनियों के सामान्य (इक्विटी) शेयरों, में किए जाने वाले निवेश के सम्बन्ध में कटौती की छूट देने का मौजूदा उपबन्ध पहली अप्रैल, 1987 से वापस लिया जाना था। नई कम्पनियों के निर्गमों को समर्थन देते रहने की आवश्यकता को देखते हुए, मैं इस रियायत को 3 और

वर्षों तक बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूँ। मैं इन श्रमिकों के धारण की अवधि को 5 वर्षों से घटाकर 3 वर्ष करने का भी प्रस्ताव करता हूँ।

82. इस समय, श्रमिकों के अन्तरण पर होने वाले पूंजीगत अभिलाभ पर दीर्घकालिक पूंजीगत अभिलाभों के लिए दी जाने वाली रियायत के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए, श्रमिकों को 36 महीनों की अवधि के लिए रखा जाना जरूरी है। श्रमधारिता की इस अवधि को घटाकर 12 महीने किए जाने का प्रस्ताव है। इससे निवेशकर्ताओं को निवेश में फेर-बदल करने की अपेक्षाकृत अधिक गुंजाइश प्राप्त होगी और श्रमिकों में लगी पूंजी की गतिशीलता में वृद्धि होगी।

83. हमारे बहुत से शहरी इलाकों में उद्योगों के केन्द्रीय-करण के कारण भीड़-भाड़, प्रदूषण और खतरों की गम्भीर समस्याएँ उत्पन्न हो गई हैं। उद्योगों को ऐसे क्षेत्रों से स्थानान्तरित करने के लिए प्रोत्साहन देने के वास्ते, मैं इन क्षेत्रों में भूमि और इमारतों की बिक्री से होने वाले पूंजीगत अभिलाभ को छूट देने का प्रस्ताव करता हूँ, बशर्ते कि इन अभिलाभों का पुनर्निवेश उद्योगों को नए स्थानों पर फिर से स्थापित करने की अनुमोदित योजनाओं में किया जाए।

84. वर्ष 1985-86 के बजट से कर की दरों में कमी किए जाने के बाद से, अल्पजन-धारित कम्पनियों के अतिरिक्त मुनाफों पर अतिरिक्त आय-कर लागू करने से संबंधित उपबंध अपनी प्रासंगिकता खो बैठे हैं। इन्हें समाप्त किया जा रहा है। कुछ अदालती फैसलों के कारण, किसी फर्म के सुनाम के अन्तरण अथवा किसी फर्म से किसी भागीदार को अथवा किसी भागीदार से फर्म को परिसम्पत्तियों के अन्तरण पर होने वाले पूंजीगत अभिलाभ कर के जाल से बच जाते हैं। ऐसे अभिलाभों को सुस्पष्ट रूप से कर-योग्य बनाया जाएगा।

85. मुक्त व्यापार क्षेत्रों में नव स्थापित उपक्रमों को कर-छूटी प्रदान की गई है। यह स्पष्ट किया जा रहा है कि यह रियायत साफ़देयर विकसित करने वाले एककों तथा निर्यात के लिए संघटकों का संयोजन अथवा उन्हें प्रोत्साहित करने वाले एककों को प्राप्त होगी।

86. तकनीकी जानकारी प्रदान करने पर किसी विदेशी राज्य अथवा किसी विदेशी उद्यम से आय अर्जित करने वाली भारतीय कम्पनियों को कर सम्बन्धी रियायत उपलब्ध है। कर में यह रियायत अब तभी उपलब्ध होगी, यदि अर्जित विदेशी मुद्रा भारत में भेजी जाएगी। यह भी स्पष्ट किया जा रहा है कि इस प्रयोजन के लिए किसी भारतीय निवासी को विदेशी उद्यम नहीं माना जा सकता।

87. कम्प्यूटरों तथा संदेशों का परिष्करण और उन्हें ग्रहण करने वाली मशीनों को आय-कर अधिनियम की अनुसूची-11 में दी गई सूची से हटा लिया जाएगा, क्योंकि ये उद्योग अब गैर-प्राथमिकता प्राप्त उद्योग नहीं हैं।

88. इस समय उन भारतीय नागरिकों को, जो विदेशों में प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए विदेशी मुद्रा में पारिश्रमिक अर्जित करते हैं, आय-कर अधिनियम की धारा 80ददक के अन्तर्गत, कतिपय शतों के अध्याधीन, 50 प्रतिशत की छूट दी जाती है। इसे और उदार बनाया जा रहा है। अब पारिश्रमिक के 50 प्रतिशत तक, अथवा रूपान्तरणीय विदेशी मुद्रा के रूप में भारत में भेजे गए पारिश्रमिक के 75 प्रतिशत तक, जो भी अधिक हो, यह छूट दी जाएगी।

89. कर-व्याप्ति का विस्तार करने और कर-अपवचन को रोकने के लिए, यह प्रस्ताव किया जाता है कि व्यावसायिक और तकनीकी सेवाओं की फीस, रायल्टी, किराए, कमीशन अथवा दलाली, और सरकार को सप्लाई की गई वस्तुओं की अदायगी के मामले में कतिपय निर्धारित राशियों से अधिक की गई अदायगियों के बारे में विनिर्दिष्ट दरों पर कर की कटौती स्रोत पर की जाए। यह व्यष्टियों और हिन्दू अविभाजित परिवारों को छोड़कर, सभी व्यक्तियों द्वारा की जाने वाली अदायगियों पर लागू होगा।

90. अब मैं कामगारों, सशस्त्र बलों के सदस्यों और विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के उपायों की ओर आता हूँ। ऐसे बहुत से मामले होते हैं, जिनमें नियोजक अपने द्वारा और कर्मचारियों द्वारा किए गए अंशदानों की राशि भविष्य निधि और राज्य बीमा निधि में जमा नहीं करते। यह भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ नियोजकों द्वारा कर्मचारियों के उपदान के सम्बन्ध में अलग निधि नहीं रखी जाती है। इस श्रमिक विरोधी प्रथा को रोकथाम के लिए, हमारा ऐसे दोषी नियोजकों को दंडित करने का प्रस्ताव है और इसके लिए यह उपबंध किया जाएगा कि इन निधियों में कर्मचारियों के अंशदान पर नियोजकों की आय के रूप में कर लगाया जाएगा और इसकी कटौती की छूट तभी दी जाएगी, जब उन्हें कानून के अन्तर्गत अनुमतय समयावधि में इन निधियों से सम्बन्धित पृथक लेखाओं में जमा करा दिया जाएगा।

91. किसी कामगार को उसकी छटनी के समय प्राप्त होने वाले मुआवजे को कर से छूट प्राप्त है। सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति की रकमों के अन्तर्गत की जाने वाली अदायगियों के मामले में भी ऐसे छूट लागू की जा रही है।

92. रेजीमेंटल निधियों अथवा गैर-पब्लिक निधियों का उपयोग युद्ध के दौरान मरने वाले सशस्त्र बलों के कामियों की विधवाओं और अपंग हो गए सैनिकों को सहायता प्रदान करने जैसे प्रयोजनों के लिए किया जाता है। इनमें किए जाने वाले अंशदानों को वही कर-रियायतें प्राप्त होंगी, जो राष्ट्रीय रक्षा कोष जैसे राष्ट्रीय महत्व के अन्य कोषों को उपलब्ध हैं।

93. मैं विकलांग व्यक्तियों और पूर्णतः नेत्रहीनों के लिए विशेष कटौती की राशि को 10,000 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए कर रहा हूँ।

94. प्रत्यक्ष करों के क्षेत्र में अन्य प्रक्रियात्मक प्रस्ताव भी हैं, जिनमें निपटारा आयोग (सेटलमेंट कमीशन) के बेहतर कार्यचालन की सुनिश्चित व्यवस्था करने के प्रस्ताव भी शामिल हैं, जो वित्त विधेयक में दिए गए हैं।

95. मैं संसद-सदस्यों के लिए निर्वाचन क्षेत्र सम्बन्धी भत्ते के सम्बन्ध में, किसी मौद्रिक सीमा की शर्त के बिना, आम छूट देने का प्रस्ताव करता हूँ।

96. उपर्युक्त प्रस्तावों से 145 करोड़ रुपए की निवल राजस्व प्राप्ति होगी।

97. अब मैं अप्रत्यक्ष करों की ओर आता हूँ। पूंजीगत वस्तुओं के टैरिफ संबंधी ढांचे का पुनर्गठन किया जाएगा और उसे युक्तिसंगत बनाया जाएगा। मेरा अधिकांश शेष क्षेत्रों पर 'मोडवाट' को लागू करने का प्रस्ताव है। कुछ उद्योगों के संबंध में उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्कों को समायोजित किया जा रहा है ताकि विकास को बढ़ावा मिल सके। आम आदमी के लिए अनेक राहतों का प्रस्ताव है।

98. जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है, पूंजीगत सामान उद्योग को विशेष समर्थन की आवश्यकता है।

99. इस समय मशीनरी के आयात के लिए दो टैरिफ दरें हैं, सामान्य मशीनरी के आयात करने के लिए 101 प्रतिशत और यदि किसी नई परियोजना के लिए मशीनरी का आयात किया जाए तो 55 प्रतिशत की रियायती दर। परियोजना आयातों के लिए शुल्क की कम दरों के फलस्वरूप अनावश्यक आयातों को बहुत बढ़ावा मिला है। सामान्य दर और परियोजना दर के बीच अंतर भी विद्यमान इकाइयों के आधुनिकीकरण के विरुद्ध भेद करता है और रूग्णता को बढ़ावा देता है। ये विसंगतियां दूर की जानी चाहिए।

100. मैं दोनों दरों को बराबर करके 85 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ। पुर्जों के लिए लागू होने वाली शुल्क दर, लागू टैरिफ दर से 15 प्रतिशत कम होगी।

101. इस समय उर्वरकों, विद्युत और इलेक्ट्रानिकी उद्योगों के लिए उनके पूंजीगत वस्तुओं के आयात पर रियायती दर पर आयात शुल्क लागू है। इन दरों को ऊपर की ओर समायोजित किया जा रहा है। इलेक्ट्रानिकी उद्योग के लिए उपस्कर के आयात पर शुल्क को 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत किया जा रहा है, उर्वरक संयंत्रों के मामले में इसे शून्य प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत किया जा रहा है। विद्युत के मामले में 50 मेगावाट क्षमता से अधिक के संयंत्रों को 25 प्रतिशत की दर से आयात किया जाता रहेगा। 50 मेगावाट और उससे कम क्षमता वाले संयंत्रों को 35 प्रतिशत की ऊंची दर पर शुल्क देना पड़ेगा।

102. विनिर्दिष्ट पूंजीगत वस्तु क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के उन्नयन को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। मैं निम्नलिखित रियायतों का प्रस्ताव करता हूँ।

(1) इस समय घरेलू पूंजीगत सामान के विनिर्माताओं को विशिष्ट प्रकार के इस्पात के आयात पर बहुत ऊंची दर पर आयात शुल्क अदा करना पड़ता है। बायलर-प्रेसर-वेसल्स-क्वालिटी प्लेटों, शीटों अथवा क्वाइलों, टरबाइन ब्लेड प्लेट्स, स्टेनलेस प्लेटों जैसे इस्पात पर शुल्क दर को कम करके 85 प्रतिशत किया जा रहा है।

(2) क्लोरोफ्लोरो मशीन उद्योग को आयातित स्टेनलेस स्टील की पूर्ति, इस समय निर्धारित 245 प्रतिशत की दर के बजाए 65 प्रतिशत की रियायती शुल्क पर की जाएगी,

(3) फाउन्डरियों के आधुनिकीकरण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, विनिर्दिष्ट पूंजीगत वस्तुओं पर आयात शुल्क को 101 प्रतिशत से कम करके 55 प्रतिशत किया जा रहा है, और

(4) कास्टिक सोडा संयंत्रों को, जो इस समय मरकरी सैल प्रौद्योगिकी पर आधारित हैं, मेम्ब्रेन सैल प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। नई प्रौद्योगिकी से ऊर्जा की बचत होती है और प्रदूषण में कमी आती है। इस बदलाव के लिए आवश्यक विनिर्दिष्ट उपस्करों को वर्तमान 101 प्रतिशत की दर की बजाए 35 प्रतिशत की रियायती शुल्क दर पर आयातों की अनुमति होगी।

103. वर्ष 1986-87 के बजट में प्रारंभ की गई मूल्य-वर्धित संशोधित कराधान प्रणाली अर्थात् "मोडवाट" एक मुख्य नया उपाय था। हमने पिछले वर्ष उत्पाद-शुल्क टैरिफ के 38 अध्यायों को इसके अंतर्गत शामिल किया था। अब मैं 'मोडवाट' को, वस्त्रोद्योग, तम्बाकू तथा पेट्रोलियम क्षेत्रों से संबंधित अध्यायों को छोड़कर शेष सभी अध्यायों पर लागू करने का प्रस्ताव करता हूँ। अब "मोडवाट" खाद्य उत्पादों, खनिज उत्पादों, चमड़े और यात्रा संबंधी वस्तुओं, जूतों, कागज और गत्ते, लकड़ी और कार्क के उत्पादों, एस्बेस्टास, सीमेंट के उत्पादों और कीमती धातुओं पर भी लागू किया जाएगा।

104. पिछले वर्ष राजस्व की स्थिरता की सुनिश्चित व्यवस्था करने के लिए "मोडवाट" प्रणाली को लागू किए जाने के साथ-साथ अंतिम उत्पाद पर लगाने वाले शुल्क में भी वृद्धि कर दी गई थी ताकि निविष्टियों पर अदा किए जाने वाले शुल्क के संबंध में जो मुजर्राई दी जा रही थी उसे संतुलित किया जा सके। इस वर्ष सिवाए कुछ एक मर्दों के अंतिम उत्पाद पर (उत्पाद की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए) शुल्क में वृद्धि नहीं की जा रही है। इस व्यवस्था से मर्दों की एक बड़ी संख्या पर शुल्क की प्रभावी दर में कमी हो जाएगी।

105. उदाहरण के लिए, खाद्य उत्पादों के मामले में, "मोडवाट" के अंतर्गत आने वाली मर्चों की कुल संख्या लगभग 100 से अधिक होगी। राजस्व में स्थिरता बनाए रखने के लिए केवल पनीर, माल्ट से बने पदार्थों और वातिन गैर-मावक पेय पदार्थों पर ही शुल्क में वृद्धि की जा रही है। अन्य खाद्य उत्पादों, जैसे कि बिस्कुटों, क्रीम रहित दूध पाउडर, मक्खन, जैम और जेली तथा मिष्ठान पदार्थों पर कराधान की प्रभावी दर में उल्लेखनीय कमी हो जाएगी। इस प्रकार के मूल्यवर्धित खाद्य उत्पादों की बिक्री के लिए उपलब्ध बाजार के विस्तार से कृषकों और उद्योग व्यवसायियों को मदद मिलेगी।

106. उन पाँच मर्चों के अंतिम शुल्क में, जिनपर पिछले वर्ष शुल्क लगाया गया था, कुछ वृद्धि आवश्यक है, खासकर ऐसे मामले में जहाँ हमने यह देखा है कि पिछले वर्ष दी गई। मुजर्राई की सुविधा शुरू में प्राक्कलिप्त सुविधा की अपेक्षा बहुत ज्यादा है। ये वस्तुएँ हैं जिन्हें आक्साइड, कृत्रिम रेजिन पर आधारित आसंजक (एडसिव), आर्गेनिक तल सक्रिय एजेंट, बिजली चालित मोटर और प्राइमरी बैटरियाँ।

107. "मोडवाट" के प्रवर्तन को सरल बनाने के लिए अनेक महत्वपूर्ण प्रक्रिया संबंधी परिवर्तन भी किए जा रहे हैं। इनमें से कुछ रियायतें इस प्रकार हैं :-

- (1) यदि विनिर्माता द्वारा कुछ खास परिस्थितियों में अंतिम उत्पाद का निर्यात किया जाए तो निविष्टि शुल्क क्रेडिट की तकद वापसी की व्यवस्था।
- (2) स्टॉक में पड़ी हुई निविष्टियों के संबंध में शुल्क क्रेडिट की उपलब्धता।
- (3) यदि निविष्टियों के वर्गीकरण में परिवर्तन हो जाने पर निविष्टियों के विनिर्माताओं से अतिरिक्त शुल्क की मांग की जाए तो निविष्टि शुल्क संबंधी क्रेडिट के समायोजन की व्यवस्था।
- (4) "मोडवाट" योजना के अंतर्गत उजरती आधार पर फुटकर काम करने वाले कार्यकर्ताओं द्वारा समस्त मर्चों के संबंध में सीधे ही निविष्टियों की प्राप्ति की अनुमति दी जाएगी।

108. इन उपायों के साथ हम उत्पाद शुल्क के प्रपाती प्रभाव को दूर करने में सफल हो सकेंगे और इस प्रकार उत्पाद-शुल्कों में काफी बड़ी राहत दे सकेंगे।

109. हमारी व्यापक नीति के कार्यक्रम में इलेक्ट्रानिकी उद्योग को तेजी से बढ़ने वाले उद्योग के रूप में माना गया है। इस उद्योग ने भारी मात्रा में रोजगार पैदा किया है। मैं कुछ ऐसे परिवर्तन करने का प्रस्ताव करता हूँ जिनसे मौजूदा नीति का आधारभूत स्वरूप सुदृढ़ होगा।

110. कम्प्यूटरों के मामले में निम्नलिखित राहते प्रदान करने और युक्तिकरणों की व्यवस्था की जा रही है :-

- (1) इलेक्ट्रानिक उप-संयोजित मर्चों पर आयात-शुल्क 308 प्रतिशत से घटाकर 150 प्रतिशत किया जा रहा है।
- (2) वृत्तकों (पेरीफरल) की सूची में अभिवृद्धि की जा रही है और 60 प्रतिशत की एक समान दर पर आयात-शुल्क निर्धारित किया जा रहा है।
- (3) विनिर्दिष्ट तथ्यांक संकलन उपस्करों पर आयात शुल्क को 140 प्रतिशत से घटाकर 100 प्रतिशत किया जा रहा है। तथ्यांक संकलन उपस्करों के यांत्रिक हिस्सों पर शुल्क को 140 प्रतिशत से घटाकर 55 प्रतिशत किया जा रहा है।
- (4) अनुसंधान संस्थानों के लिए कम्प्यूटर पेरीफरल पर आयात-शुल्क में छूट देने से संबंधित वर्तमान अधिसूचना के प्रवर्तन की अवधि को तीन वर्ष के लिए और बढ़ाया जा रहा है।
- (5) खुली सामान्य लाइसेंस प्रणाली के अंतर्गत आयातित कम्प्यूटर सिस्टमों पर लगने वाले शुल्क को 150 प्रतिशत से घटाकर 140 प्रतिशत किया जा रहा है (शुन्यादी और सहायक)।
- (6) कम्प्यूटरों के विनिर्दिष्ट इलेक्ट्रानिकी हिस्सों पर आयात शुल्क को, स्वदेशी उत्पादन को समुचित संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 75 प्रतिशत किया जा रहा है। कम्प्यूटर पेरीफरल के यांत्रिकी हिस्सों पर लगने वाले आयात-शुल्क को भी 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 75 प्रतिशत किया जा रहा है और इसे सी. एन. सी. सिस्टम के यांत्रिकी हिस्सों पर भी लागू किया जा रहा है।

111. पिछले वर्ष भारतीय कम्प्यूटर उद्योग ने 225 करोड़ रुपए का कारोबारी उत्पादन किया। यह उद्योग अपनी शोषावस्था से निकल चुका है और अब स्वस्थ और सशक्त है। अब चूंकि यह उद्योग परिपक्व अवस्था में पहुंच गया है इसलिए कर वसूल करने वाले भी पीछे नहीं रह सकते। इसलिए कम्प्यूटरों और पेरीफरल पर 10 प्रतिशत की दर से उत्पाद-शुल्क लगाए जाने का प्रस्ताव है। "मोडवाट" के कारण शुल्क का प्रभावी भार अपेक्षितया कम ही रहेगा।

112. इलेक्ट्रानिकी उद्योग की दीर्घावधिक सफलता के लिए इस उद्योग का अनुसंधान तथा विकास विषयक आधार भी निर्णायक महत्व रखता है। इसलिए मैं अनुसंधान तथा विकास कार्यों के लिए आवश्यक विनिर्दिष्ट उपस्करों पर शुल्क को 140 प्रतिशत से कम करके 55 प्रतिशत किए जाने का प्रस्ताव करता हूँ।

113. हमें इलेक्ट्रानिकी उद्योग के लिए आवश्यक पूंजीगत वस्तुओं के स्वदेशी उत्पादन को अवश्य प्रोत्साहित करना चाहिए। इस समय ऐसी पूंजीगत वस्तुओं के विनिर्माण के लिए आवश्यक यांत्रिकी संघटकों पर 140 प्रतिशत की दर से शुल्क लगाया जाता है। मैं लगभग 300 विनिर्दिष्ट मशीनों के लिए आवश्यक संघटकों के मामले में इस शुल्क को घटाकर 45 प्रतिशत कर दिए जाने का प्रस्ताव करता हूँ।

114. सामान्य इलेक्ट्रानिकी के क्षेत्र में कच्चे माल, अलग अलग हिस्सों और संघटकों के आयात पर क्रमशः 30 प्रतिशत, 45 प्रतिशत और 75 प्रतिशत की दर से रियायती शुल्क की सुविधा उपलब्ध है। हम इस रियायती शुल्क सुविधा की व्याप्ति के क्षेत्र को, इसमें कुछ और मदों को शामिल करके बढ़ा रहे हैं।

115. मैं सभी शुल्कों में पाली सिलिकान के उत्पादन पर लगाए जाने वाले उत्पाद-शुल्क को समाप्त करने का प्रस्ताव रख रहा हूँ। यह प्रस्ताव स्वदेशी उद्योग को समर्थन देने के लिए है। सिलिकान, मोर मेलों और फोटोवाल्टेयिक सिस्टमों के आयात पर क्रमशः 30 प्रतिशत, 45 प्रतिशत और 75 प्रतिशत की दरों से सीमा शुल्क लगाया जाता है। मैं स्वदेशी उत्पादन के हित को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रानिकी उद्योग के लिए पाली सिलिकान के आयात पर लगने वाले शुल्क को बढ़ाकर 75 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ।

116. टेलीविजन सेटों के उत्पादन में, उत्पादन लक्ष्यों के अनुरूप बड़ी तेजी से वृद्धि हुई है। इस प्रकार एक बड़ा सजीव और प्रतियोगिता सक्षम उद्योग देश में सुस्थापित हो गया है। मैं दो परिवर्तन करने का प्रस्ताव करता हूँ:

- (i) कर अपवंचन विरोधी उपाय के रूप में 36 सेंटीमीटर से बड़े आकार के सेटों के लिए उपयोग में लाई जाने वाली थ्याम-स्वैत ट्यूबों पर 150 रुपए का उत्पादन-शुल्क अथवा प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाने का प्रस्ताव है और समस्त रंगीन टेलीविजन ट्यूबों पर 600 रुपए का उत्पादन-शुल्क अथवा प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाने का प्रस्ताव करता हूँ। 'मोडवाट' के अंतर्गत शुल्क अदा करने वाले विनिर्माताओं को इस निविष्टि शुल्क की पूरी कटौती दी जाएगी, और उपभोक्ता पर अतिरिक्त शुल्क का कोई बोझ नहीं पड़ेगा। किन्तु इससे बिना लाइसेंस का उत्पादन रोकने में मदद मिलेगी।
- (ii) इस समय 36 सेंटीमीटर से बड़े आकार के रंगीन टेलीविजन पर, टेलीविजन सेट के मूल्य को अनपेक्षित करते हुए 1500 रुपए का उत्पादन शुल्क लगता है। मैं महंगे सेटों पर शुल्क को बढ़ाकर 1750 रुपए प्रति सेट करने का प्रस्ताव करता हूँ। यह व्यवस्था 5000 रुपए से अधिक निर्धारण योग्य मूल्य पर तैयार किए जाने वाले सेटों पर

लागू होगी जो कि लगभग 7500 रुपए की खुदरा मूल्य के अनुरूप बैठेगी। 5000 रुपए या उससे कम के निर्धारण-योग्य मूल्य पर तैयार किए जाने वाले सेटों पर उत्पादन-शुल्क 1500 रुपए ही रहेगा। महंगे सेट अतिरिक्त शुल्क का भार वहन कर सकते हैं।

117. इलेक्ट्रानिकी उद्योग से संबंधित इन प्रस्तावों से 19.30 करोड़ रुपए के राजस्व की निवल हानि होगी। उत्पाद-शुल्कों से 40 करोड़ रुपए की राजस्व वृद्धि होगी और सीमा-शुल्कों के राजस्व में 59.30 करोड़ रुपए का घाटा होगा।

118. पिछले कुछ वर्षों में आटोमोबाइल उद्योग के क्षेत्र में महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं। नई प्रौद्योगिकी लागू की गई है, उत्पादन में वृद्धि हुई है और स्वदेशीकरण हो रहा है। सरकार इन बातों और अन्य घटनाओं की समीक्षा कर रही है और इस संबंध में एक व्यापक नीति की घोषणा करेगी। फिलहाल आटोमोबाइल उद्योग के लिए मेरे प्रस्ताव इस प्रकार हैं:-

- (i) कम ईंधन की खपत वाले ट्रकों, कारों और दुपहिया वाहनों के संघटकों के विनिर्माण के लिए आवश्यक आयातित उप-संघटकों पर इस समय 50 प्रतिशत की रियायती दर से सीमा-शुल्क लगाया जाता है। मैं ऐसे संघटकों की सूची को और बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूँ, जिनके लिए उप-संघटकों के रियायती आयात की व्यवस्था है। इससे स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा।
- (ii) ईंधन की कम खपत वाले ऐसे मोटर वाहनों के उत्पाद-शुल्क को, जिनकी इंजन क्षमता 1000 सी. मी. से अधिक नहीं है, 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत किए जाने का प्रस्ताव है। यह क्षेत्र अतिरिक्त शुल्क का भार सहन कर सकता है और यह क्षेत्र शेष उद्योग की तुलना में कम दर होने पर भी लाभ में ही रहेगा।
- (iii) मेरा प्रस्ताव है कि विकलांग व्यक्तियों के मामले में अधिकतम 1000 सी. सी. क्षमता के इंजन वाली कम ईंधन की खपत करने वाली कारों में संयोजित किए जाने वाले स्वचल ट्रांसमिशन व अन्य विशेष उपस्कर के संबंध में सीमा-शुल्कों से पूरी छूट दे दी जाए।
- (iv) कम ईंधन की खपत वाले मोटर वाहनों के विक्रय के उपरांत की कारवाई अथवा गारंटी को पूरा करने के लिए फालतू पुर्जों के आयात पर शुल्क की दर को 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 75 प्रतिशत किया जा रहा है।

- (v) अब ट्रैक्टरों पर उत्पादन-शुल्क पावर, टेक ग्राफ हास पावर के बजाय इंजन क्षमता के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। ऐसा कर अपवर्चन उपाय के रूप में किया जा रहा है जिससे राजस्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

119. जन साधारण द्वारा प्लास्टिक का उपयोग व्यापक रूप से किया जाता है। खेती और कारखानों में इसके उपयोग की भारी संभावनाएं विद्यमान हैं। हमारे प्लास्टिक की कीमतें बहुत ऊंची हैं। सरकार, इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में लागत को कम करने के उपाय शुरू करने का विचार रखती है।

120. मैं, पी. वी. सी. रेजिन पर (सामान्य प्रयोजनीय सस्पेंशन ग्रेड) बुनियादी सीमा-शुल्क को 10,500 रुपए प्रति मी. टन से घटाकर 7,500 रुपए प्रति मी. टन. करने का प्रस्ताव करता हूं। इन रेजिनों को सस्ते जूतों और कृषि क्षेत्र के लिए उपयोग में लाए जाने वाले पाइपों के विनिर्माण में और तारों तथा केबलों को कवचित करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है।

121. मैं निम्न घनत्व की पॉलिथिलीन पर बुनियादी सीमा शुल्क को 100 प्रतिशत से घटाकर 75 प्रतिशत करने का प्रस्ताव भी कर रहा हूं। निम्न घनत्व की पॉलिथिलीन का बहुत अधिक किस्मों की पैकेजिंग सामग्री के उत्पादन के लिए एक आधार के रूप में इस्तेमाल में लाया जाता है। निम्न घनत्व की पॉलिथिलीन फिल्मों को नहरों और खेतों या जोतों तक पहुंचने वाले रजवाहों में अस्तर लगाने के लिए इस्तेमाल में लाए जाने की भारी संभावनाएं हैं।

122. पुनः सुजित सेलूलोज के उत्पादों पर लगाने वाले उत्पाद-शुल्क को, जिसमें सस्ती पैकेजबंदी सामग्री सेलोकन भी सम्मिलित है, 40 प्रतिशत से घटाकर 20 प्रतिशत किया जा रहा है। इसी तरह से सेलूलोज एसिटेड मोडिफाईड ग्रेन्यूल पर भी, जिसे चश्मों के फ्रेम, छतरियों के मुट्ठे और दांत साफ करने के ब्रश तयार करने के काम में इस्तेमाल किया जाता है तथा सोडियम कारबोक्सी मिथाइल सेलूलोज के उत्पाद शुल्क को भी कम किया जा रहा है, जिसका उपयोग तेल की खोज के लिए भू-छेदन का कार्य करने, वस्त्रों के संसाधन और प्रक्षालन सामग्री (डिटर्जेंट) के विनिर्माण में किया जाता है।

123. कतिपय वर्गों के औद्योगिक प्लास्टिक, एक्रिलिक और बिनाइल रेजिन एमल्शन पर उत्पाद-शुल्क को 40 प्रतिशत से घटाकर 20 प्रतिशत किया जा रहा है।

124. पिछले वर्ष में हमने राजकोषीय तथा अन्य साधनों के माध्यम से अपने निर्यात व्यापार को सुदृढ़ करने के बहुत से उपाय किए हैं। मैं निम्नलिखित अतिरिक्त प्रस्ताव देने के लिए प्रस्ताव करता हूं :-

- (क) जवाहरात और जड़ाऊ आभूषण उद्योग के लिए—
औजारों और मशीनों के अंतर्गत 46 अतिरिक्त

मदों पर सीमा-शुल्क को घटाकर 35 प्रतिशत किया जा रहा है।

- (ख) समुद्री-उत्पाद उद्योग के लिए — तीन अतिरिक्त मदों पर 40 प्रतिशत की रियायती दर से (बुनियादी और सहायक शुल्क) आयात-शुल्क लगाया जाएगा।

- (ग) चमड़ा उद्योग के लिए —

- (i) चमड़ा उद्योग के लिए आवश्यक मशीनों की 31 अतिरिक्त मदों पर शुल्क की रियायती दर 35 प्रतिशत होगी,

- (ii) तैयार चमड़े को परिष्कृत करने के लिए इस्तेमाल में लाई जाने वाली पॉलिथिथेन फिल्म/फायल पर 40 प्रतिशत की कम दर के हिसाब से प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगेगा।

- (iii) निर्यात किए जाने के लिए फुटबालों के विनिर्माण के काम में आने वाले पॉलीथिथेन लेदर पर शुल्क से छूट दी जाएगी।

- (घ) टायरों के लिए—निर्यात उत्पादन के लिए आवश्यक टायर मोल्डों पर आयात शुल्क को घटाकर 25 प्रतिशत किया जा रहा है।

- (ङ) अवशिष्ट अभ्रक और छीजन को छोड़कर अभ्रक के उत्पादों पर निर्यात शुल्क समाप्त किया जा रहा है।

- (च) लेक्स और रेमीफाइबर पर आयात शुल्क को 80 प्रतिशत से घटाकर 40 प्रतिशत किया जा रहा है।

125. मैं कुछ समायोजन करने का भी प्रस्ताव करता हूं, जिससे जनसाधारण को और फायदा होगा :-

- (1) अगस्त, 1985 में सरकार ने कम खर्चोंले मिश्रित फेब्रिक (सुलभ वस्त्रों) के विनिर्माण के संबंध में राजकोषीय राहत देने की एक योजना शुरू की थी। इस योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय वस्त्रोद्योग निगम की मिलों को 45 रुपए प्रति मीटर तक के मूल्य के सूट के कपड़े और 20 रुपए प्रति मीटर तक के मूल्य के कमीज बनाने लायक कपड़ों के विनिर्माण के लिए बिना उत्पाद-शुल्क लगाए कच्चा माल मुहैया किया जाता है। इस योजना की अच्छी शुरुआत हुई है। सीमांत साड़ियों के विनिर्माण के लिए भी ऐसी ही एक योजना शुरू किए जाने का प्रस्ताव है। इसके फलस्वरूप मुनासिब कीमतों पर अच्छी किस्मों की साड़ियां उपलब्ध हो सकेंगी।

- (2) इन राम 45 कारा फी जोड़े मूल्य के जूते पर उत्पाद शुल्क नहीं लगता । मैं इस सीमा को फी जोड़ा बढ़ाकर निर्धारण मूल्य के 60 रुपये के बराबर करना चाहता हूँ जो कि लगभग 100 रुपया फी जोड़े के वर्ग के जूतों के अनुरूप है । उत्पाद शुल्क में होने वाली हानि को प्रतिसंतुलित करने के लिए, इससे अधिक निर्धारण-योग्य मूल्य के जूतों पर, चमड़े के जूतों के संबंध में उत्पाद शुल्क को बढ़ाकर 15 प्रतिशत और कृत्रिम रेजिन के जूतों के संबंध में 20 प्रतिशत किया जा रहा है ।
- (3) 10,000 रुपया प्रति मीट्रिक टन से अधिक मूल्य के जनता साबुन पर 5 प्रतिशत की कम दर पर उत्पाद-शुल्क लगता है । मैं मूल्य-सीमा को बढ़ाकर 12,000 रुपया प्रति मीट्रिक टन तक कर देने का प्रस्ताव करता हूँ । इससे नहाने और कपड़े धोने के काम आने वाले सस्ते साबुन की लागत कम हो जाएगी । 12,000 रुपये प्रति मीट्रिक टन से लेकर 25,000 रुपये प्रति मीट्रिक टन तक के मूल्य के साबुन पर 15 प्रतिशत की दर से शुल्क की श्रदायगी की जाती रहेगी, किन्तु महंगे साबुनों पर, जिनका मूल्य 25,000 रुपये प्रति मीट्रिक टन से ऊंचा होगा, 25 प्रतिशत की दर से शुल्क लिया जाएगा ।
- (4) अधिक में अधिक 40 रुपया प्रति वर्गमीटर के निर्धारण-योग्य मूल्य के शोड़ी ऊन के कपड़ों पर उत्पादन-शुल्क से पूरी छूट उपलब्ध है । मैं इस सीमा को बढ़ाकर 60 रुपया प्रति वर्गमीटर करने का प्रस्ताव रखता हूँ । शोड़ी कम्बलों पर पहले से ही उत्पाद-शुल्क से पूरी छूट दी जा रही है ।
- (5) ब्लूरेसैंट ट्यूबों पर उत्पाद-शुल्क को घटाकर मातानुसार 2 रुपया प्रति ट्यूब किया जा रहा है । ऐसी ट्यूबों के अन्य संलग्नकों और हिस्सों पर भी 10 प्रतिशत की घटी हुई दर से उत्पाद-शुल्क देना होगा ।
- (6) मैं जैव-गैस उपकरणों जैसे स्टोव, हाट प्लेट और लाइट को भी उत्पाद शुल्क से छूट दिए जाने का प्रस्ताव कर रहा हूँ । इससे जैव-गैस के अधिक उपयोग को प्रोत्साहन मिलेगा ।
- (7) इस समय विनिर्दिष्ट जीवन-रक्षक उपस्करों पर सीमा-शुल्क से पूरी छूट प्राप्त है, किन्तु ऐसे उपस्करों के लिए आवश्यक फ़ालतू पुर्जों के आयात पर शुल्क लगता है । यह शुल्क हमारे अस्पतालों और चिकित्सालयों पर एक गैर-जरूरी बोझ है । मैं ऐसे जीवन-रक्षक उपस्करों के लिए आवश्यक फ़ालतू पुर्जों और सहायक पुर्जों पर शुल्क से पूरी छूट देने का प्रस्ताव करता हूँ ।

- (8) नोटबुक, लेटर पैड, क्वार्टिंग पैड, रजिस्ट्रों, लेखा-पुस्तकों और फ़ाइल कवर जैसी मदों पर उत्पाद-शुल्क से पूरी छूट दी जा रही है ।

126. सूती वस्त्रों के संबंध में मैं दो प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ :—

- (1) मैं हाथ से तैयार किए जाने वाले कपड़े के संबंध में 36 लाख वर्गमीटर की संपूर्ण छूट-प्राप्त सीमा को बढ़ाकर 50 लाख वर्गमीटर कर देने की व्यवस्था करके छोटे पैमाने पर हाथ से तैयार किए जाने वाले कपड़ों की योजना को और उदार बनाने का प्रस्ताव करता हूँ ।
- (2) विद्युत संसाधक क्षेत्र में तैयार किए जाने वाले सूती कपड़ों के उत्पादन-शुल्क की व्यवस्था को भी युक्तिसंगत बनाया जा रहा है । 25 रुपया प्रति वर्गमीटर तक के मूल्य के कपड़ों के संबंध में उत्पाद-शुल्क की मातानुसार दरें निर्धारित की जा रही हैं । इससे 15 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि होगी ।

127. मैं ऊन के गोलों पर संपूर्ण रूप से उत्पाद शुल्क समाप्त करने का प्रस्ताव करता हूँ, किन्तु मैं कच्ची ऊन, ऊन के टुकड़ों और रही ऊन के सीमा-शुल्क को बढ़ाकर 20 प्रतिशत से 30 प्रतिशत कर देने और कृत्रिम टुकड़ों के सीमा-शुल्क को 80 प्रतिशत से घटाकर 30 प्रतिशत कर देने का प्रस्ताव भी कर रहा हूँ । पॉलिएस्टर ऊन मिश्रित यार्न पर उत्पाद-शुल्क को 30 रुपये प्रति किलोग्राम से घटाकर 15 रुपये प्रति किलोग्राम किए जाने का प्रस्ताव है । इससे सस्ती किस्मों के ऊनी कपड़ों का लाभ होगा ।

128. विस्कोस स्टेपल फाइबर और विस्कोस फ़िलामेंट यार्न पर शुल्क की वर्तमान दरों में कई वर्षों से कोई संशोधन नहीं किया गया है । राजस्व उपार्जक उपाय के रूप में, मैं विस्कोस स्टेपल फाइबर पर लगने वाले उत्पाद शुल्क की दर को 5 रुपया प्रति किलोग्राम से बढ़ाकर 7 रुपया प्रति किलोग्राम कर देने का प्रस्ताव कर रहा हूँ । इसी तरह से विस्कोस फ़िलामेंट यार्न के उत्पाद शुल्क की मौजूदा दर में भी करीब 12.5 प्रतिशत की वृद्धि की जा रही है । इन दोनों उपायों से 29 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा ।

129. जैसा कि सदन को मालूम है एक ऐसी योजना चल रही है जिसके अन्तर्गत चीनी, तम्बाकू, और वस्त्रों पर बिक्री कर के स्थान पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (ए. ई. डी.) लगाया जाता है । अतिरिक्त उत्पादशुल्क से प्राप्त होने वाली पूरी राशि राज्य सरकारों को दे दी जाती है । अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क को बढ़ाए जाने की आवश्यकता है ताकि कर भार सम्मत स्तर तक पहुंच जाए । 100 रुपया प्रति वर्ग मीटर से अधिक निर्धारण योग्य मूल्य के महंगे कपड़ों पर शुल्क की दर बढ़ाकर 20 प्रतिशत की जा रही है ।

इस अनिश्चित उत्पाद-शुल्क से कुल 40 करोड़ रुपये के राजस्व का लाभ होगा और इसे पूर्णतः राज्य सरकारों को दे दिया जाएगा।

130. मैं अब कुछ अन्य उद्योगों की चर्चा करूँगा, जिन्हें राहत की आवश्यकता है:—

- (1) हाल की नीतियों के परिणामस्वरूप सीमेंट के उत्पादन में वृद्धि हुई है जिससे उपभोक्ता को लाभ पहुँचा है और इस नीति ने सीमेंट के बिक्रय बाजार को क्रय बाजार में परिवर्तित कर दिया है। इस उद्योग में नए एककों की ऊँची पूँजी लागतों को देखते हुए इसे कुछ समर्थन प्रदान किए जाने की जरूरत है। अतः मैं पोर्टलैंड सीमेंट के संबंध में उत्पाद-शुल्क में 50 रुपये प्रति मीट्रिक टन की छूट देने का प्रस्ताव करता हूँ जिसका उत्पादन इन एककों द्वारा 1-4-1986 से अथवा उसके बाद किया जा रहा हो। यह छूट 1-3-1987 से तीन वर्ष के लिए उपलब्ध रहेगी। इन एककों के संबंध में लेवी कोटा को वर्तमान 30 प्रतिशत के स्तर से घटाकर 15 प्रतिशत किया जा रहा है। सीमा-शुल्क में छूट केवल उन एककों को ही उपलब्ध होगी जिनका कुल उत्पादन उसकी साइसेंस क्षमता के 30 प्रतिशत से कम न हो।
- (2) मैं विलायक-निष्कषिक तेलों और खनी की उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए विशिष्ट मशीनों का आयात 55 प्रतिशत की सीमा-शुल्क छूट प्राप्त दर पर करने की अनुमति देने का प्रस्ताव करता हूँ। पिछले वर्ष हमने वनस्पति और साबुन के लिए गौण तेलों का अधिक मात्रा में उपयोग करने के लिए उत्पाद-शुल्क में छूट देने की एक प्रणाली लागू की। इस व्यवस्था का वांछित परिणाम निकला और चाबल की भूसी के तेल के उत्पादन में तथा वनस्पति और साबुन के उत्पादन में इनके उपयोग में पर्याप्त वृद्धि हुई। छूट की योजना को इस वर्ष भी जारी रखा जा रहा है। कुछ प्रक्रिया संबंधी परिवर्तन किए जा रहे हैं और वनस्पति पर मूल्यानुसार शुल्क के स्थान पर मात्रानुसार शुल्क लगाया जा रहा है।
- (3) खाद्य पदार्थों का बेहतर पैकेज बंधन और बेहतर संसाधन हमारे देश के किसानों की अप्रमदनी में वृद्धि करने के लिए बहुत सहायक सिद्ध हो सकता है। मैंने प्लास्टिक के बारे में बहुत सहायक प्रस्ताव किए हैं जो बहुत सहायक सिद्ध होंगे। मैं मशीनरी की कुछ विनिर्दिष्ट मर्दों तथा निविषाक्त पैकेजबंदी की मर्दों पर आयात शुल्क को 101 प्रतिशत से और ज्यादा कम करके 50 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ।

- (4) मैं औषधों के विनिर्माण में अनन्य रूप से अथवा प्रधान रूप से उपयोग में लाए जाने वाले 36 और अधिक मध्यवर्ती औषधों पर अनिश्चित सीमा शुल्क की छूट देने का प्रस्ताव करता हूँ। इसके अनिश्चित मैं पाइराजिमाइड के विनिर्माण में, जो क्षय रोग दूर करने वाली एक दवा है, उपयोग में लाए जाने वाले दो विनिर्दिष्ट मध्यवर्ती औषधों पर सीमा-शुल्क को कम करके 70 प्रतिशत करने का प्रस्ताव कर रहा हूँ।
- (5) ताप-सह सामग्री के निर्माण के काम में आनेवाले विनिर्दिष्ट कच्चे मान पर सीमा शुल्क घटाया जा रहा है।
- (6) सी.जी.प्रेड के असाधित एल्यूमीनियम पर उत्पाद शुल्क को 13 प्रतिशत से घटाकर 11 प्रतिशत किए जाने का प्रस्ताव है।
- (7) मैं, ध्वनि अंकित (डब्ब) वृत्त चित्रों सहित सामान्य वृत्त चित्रों पर उत्पाद-शुल्क में इस समय प्रवृत्त शुल्क दर में लगभग 10 प्रतिशत की कमी करने का प्रस्ताव करता हूँ।
- (8) औद्योगिक प्रयोजनों के लिए अनन्य रूप से उपयोग में लाए जाने के उद्देश्य से आयात किए जाने वाले विनिर्दिष्ट क्षमता के ड्रिनेचर्ड एथाइल प्रलोहल को 60 प्रतिशत मूल्यानुसार से अधिक सीमा-शुल्क से छूट दी जा रही है।
- (9) रेफ्रिजेशन (प्रशीतन) और वातानुकूलन उपकरणों तथा मशीनी उद्योग से संबंधित छोटे पैमाने के उद्योगों की दवा अलग-अलग मौजूदा योजनाओं को मिलाकर एक योजना बनाए जाने व इसे उदार बनाने का प्रस्ताव है। अब पांच लाख रुपये तक की निकासियों पर उत्पाद-शुल्क से पूरी छूट होगी। उसके बाद पांच लाख रुपये से लेकर पंद्रह लाख रुपये तक के बीच की निकासियों के लिए प्रवृत्त उत्पाद-शुल्क के 50 प्रतिशत के बराबर उत्पाद-शुल्क लगाया जाएगा। बाद में, एकक सामान्य शुल्क की अदायगी करेगा किन्तु एकक के लिए उपलब्ध छूट और रियायतों को बनाए रखने की पात्रता की सीमा 40 लाख रुपये तक होगी।
- (10) मैं एक. बी. आई/स्पंज लॉहे और इस्पात के पिघलने योग्य टुकड़ों के संबंध में इलेक्ट्रिक आर्क भट्टी एककों को उपलब्ध सीमा-शुल्क की 20 प्रतिशत की रियायती दर का इंडक्शन फ़ारनेस एककों पर भी लागू करने का प्रस्ताव करता हूँ।

(11) एल्यूमीनियम फ़्लोराइड के विनिर्माण में इस्तेमाल लाए जाने वाले फ्लूस्पर (प्राकृतिक कैल्शियम फ्लोराइड) पर सीमा-शुल्क को 110 प्रतिशत से घटाकर 75 प्रतिशत किया जा रहा है।

(12) मैं, परिवार नियोजन उपकरणों और उपस्करों के विनिर्माण के लिए आवश्यक संयंत्र और उपस्करों के संबंध में और साथ ही गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करने वाले उपस्करों के संबंध में सीमा-शुल्क को घटाकर 25 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ। केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्रों तथा स्थानीय निकायों द्वारा प्रशासित अग्निशमन सेवाओं के लिए उपयोग में लाए जाने वाले अद्यतन किस्मों के अग्निशमन उपस्करों पर भी इतनी ही कम दर पर शुल्क लगाया जा रहा है।

131. अतिरिक्त राजस्व की खोज करने में, मुझे वित्त मंत्रियों के हमेशा भरोंसे योग्य और विश्वसनीय मित्र और स्वास्थ्य मंत्रियों के पक्के शत्रु का सहारा लेना पड़ा है। हाल में, मुझे बताया गया है कि विवादों और मुकदमेबाजी के कारण ये मित्रतापूर्ण संबंध बिगड़ गए हैं। अब मेरा प्रस्ताव है कि उत्पाद-शुल्क लगाने की एक नई और अधिक युक्तिसंगत प्रणाली अपना कर इन दोनों के बीच मित्रता की पुनःस्थापना की जाए।

132. सिगरेटों पर उत्पाद-शुल्क की मौजूदा प्रणाली मुद्रित खुदरा कीमतों पर आधारित है। मेरा मानानुसार उत्पाद-शुल्क की एक बिल्कुल नई प्रणाली अपनाने का प्रस्ताव है, जो सिगरेटों की लम्बाई पर आधारित होगी। यह प्रणाली बहुत से देशों में प्रचलित है। इससे उत्पाद-शुल्क के सुस्पष्ट निर्धारण की सुनिश्चित व्यवस्था हो जाती है और निर्धारण योग्य मूल्य अथवा बिक्री मूल्य का निश्चय करने की सभी समस्याओं से बचा जा सकता है।

133. यह प्रस्ताव है कि 70 मि.मी. तक के आकार के बिना-फिल्टर वाले सिगरेट के लिए उत्पाद-शुल्क की दर 150 रुपए प्रति 1000 सिगरेट होगी। फिल्टर वाले सिगरेटों के मामले में, उत्पाद-शुल्क के चार खंड होंगे, अर्थात् 70 मि.मी. से अधिक 75 मि.मी. तक, 75 मि.मी. से अधिक 85 मि.मी. तक, और 85 मि.मी. से अधिक 100 मि.मी. तक। इन खंडों में फिल्टर वाले प्रति हजार सिगरेटों पर उत्पाद-शुल्क की दर क्रमशः 200 रुपए, 300 रुपए, 400 रुपए और 600 रुपए होगी। सिगरेटों की टैरिफ दर 700 रुपए है, और इसलिए 70 मि.मी. से अधिक लम्बे बिना फिल्टर वाले सिगरेटों और 100 मि.मी. से अधिक लम्बे फिल्टर वाले सिगरेटों पर टैरिफ दर लागू होगी।

134. यह योजना सरलीकरण और युक्तिकरण का एक प्रमुख उपाय होगी। प्रसंगवश, इससे सरकार को 200 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व भी प्राप्त होगा।

135. अब मैं मुख्यतः युक्तिकरण के कुछ अन्य उपायों का उल्लेख करूंगा।

(1) वनों की कटाई के कारण हमारे पर्यावरण को गम्भीर क्षति पहुँच रही है। कर ढाँचे में हमारी वन सम्पत्ति के संरक्षण में योगदान मिलना चाहिए। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हमने लकड़ी के उत्पादों पर लगने वाले शुल्क के ढाँचे को युक्तिसंगत बनाया है। मैं अपशिष्ट लकड़ी पर आधारित लकड़ी के उत्पादों जैसे पार्टिकल बोर्डों, इंसुलेशन और हार्ड बोर्डों और फाइबर बोर्डों पर 20 प्रतिशत की एक-समान दर से उत्पाद-शुल्क लागू करने का प्रस्ताव करता हूँ। प्राइम टिम्बर से बने सभी प्रकार के प्लाई-वुड पर 30 प्रतिशत की ऊँची दर लागू होगी। मैं माननीय सदस्यों और पर्यावरण के संरक्षण में रुचि रखने वाले अन्य व्यक्तियों से अपने सुझाव देने का अनुरोध करता हूँ, और मैं ऐसे अन्य उपाय करने को तैयार हूँ जिनसे इस नीति विषयक उद्देश्य का कार्यान्वयन हो सकता हो।

(2) नसबंद और खाने के तम्बाकू पर और ऐसे उत्पादों पर जिनमें खाने का तम्बाकू मिला हो, 25 प्रतिशत की दर से उत्पाद-शुल्क लागू किया जा रहा है।

(3) सीमा-शुल्कों में छूट की अनेक अधिसूचनाओं के परिणामस्वरूप बहुत सी मदों के लिए शुल्क की दर 25 प्रतिशत से कम हो गई है। बीजक संबंधी कदाचारों की रोकथाम करने के लिए, शुल्क की दर, अत्यन्त विशेष परिस्थितियों को छोड़ कर, 25 प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए। तदनुसार, 7 मदों के लिए शुल्क की दरें बढ़ा कर 25 प्रतिशत की जा रही हैं। कुछ अन्य मामलों में शुल्क की दरों का पुनरीक्षण किया गया है और उनमें वृद्धि की गई है।

(4) सोडा पेश के बारे में 25 प्रतिशत (युनिटादी) की रियायती दर 31 मार्च, 1988 तक जारी रहेगी।

(5) यांत्रिक और क्वार्टेज एनालाग वाली हाथ की घड़ियों के 13 विनिर्दिष्ट हिस्सों पर 70 प्रतिशत की रियायती दर, कतिपय आशोधनों के साथ, एक और वर्ष तक जारी रहेगी। तीन विनिर्दिष्ट हिस्सों के लिए शुल्क की दर बढ़ा कर 100 प्रतिशत की जा रही है। हाथ की घड़ियों के कुछ अन्य हिस्सों के सम्बन्ध में रियायती दर बिल्कुल वापस ली जा रही है।

(6) वातित मृदु (साफ्ट) पेय पर उत्पाद-शुल्क में 20 पैसे प्रति बोतल और सोडे के मामले में 15 पैसे प्रति बोतल की वृद्धि की जा रही है। बोतलों से भिन्न पैकेजिंग में सोडे और मृदु पेयों पर क्रमशः 60 प्रतिशत और 75 प्रतिशत की दर से शुल्क लगेगा। अब इन मदों को मोडवाट के लाभ प्राप्त होंगे और इसलिए प्रभावी भार काफी कम होगा।

(7) विभिन्न किस्मों के संसाधित (प्रांसेस्ड) खाद्यों पर 15 प्रतिशत की दर से उत्पाद-शुल्क लिया जाता है। इस प्रकार के संसाधित और अपेक्षा-कृत महंगे पैकेजबंद खाद्यों की सूची में नूडल, स्पेहेटी, मेकरोनी, वर्मीसेली, दालों से भिन्न अनाजों के पनेक, पकाने के लिए तैयार खाद्य मिश्रण, आदि को शामिल किया जा रहा है, जिन्हें यूनिट कंटेनरों में बिक्री के लिए प्रस्तुत किया जाता है।

(8) अनपिटे एल्यूमिनियम पर, सामान्य अतिरिक्त शुल्क के अलावा, बुनियादी सीमा-शुल्क की मूल्यानुसार दर को 20 प्रतिशत से बढ़ा कर 35 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है। आयातित धातु की जहाज-उत्तरती लागत को सांविधिक प्रति टन मूल्य के बराबर करने के लिए स्वदेशी एल्यूमिनियम की कीमतों में वृद्धि कर दिए जाने के कारण ऐसा करना जरूरी हो गया है।

(9) मैं लघु इस्पात संयंत्रों द्वारा निमित्त इस्पात के डलों पर लगने वाले उत्पाद-शुल्क को 315 रुपए प्रति टन से बढ़ा कर 365 रुपए प्रति टन करने का प्रस्ताव करता हूं, ताकि यह शुल्क एकीकृत इस्पात संयंत्रों द्वारा उत्पादित इस्पात के डलों के शुल्क के बराबर हो जाए। लेकिन मोडवाट क्रेडिट और ऊंची कीमतों के कारण, संशोधित दर पर भी उत्पाद शुल्क का मूल्यानुसार प्रभाव एकीकृत इस्पात संयंत्रों द्वारा उत्पादित इस्पात पर लगने वाले शुल्क से कम होगा।

136. मैं इस अवसर का उपयोग तेल पूल खाने के अधिशेष को कर-जाल के अन्तर्गत लाने के लिए कर रहा हूं। इससे उपभोक्ता मूल्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह अधिशेष इस समय सरकार को कर-भिन्न प्राप्ति के रूप में प्राप्त होता है। मैं अब आयातित क्रूड पेट्रोलियम पर सीमा-शुल्क में 500 रुपए प्रति मीट्रिक टन की वृद्धि करने का प्रस्ताव करता हूं। मैं उन उच्चतम सीमाओं को भी बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूं, जहां तक, तेल उद्योग ने विकास के लिए भारत में उत्पादित क्रूड तेल और प्राकृतिक गैस पर उपकर के रूप में उत्पाद-शुल्क लगाया जा सकता है। इन सीमाओं को क्रूड तेल के मामले में 300 रुपए प्रति

मी. टन से बढ़ा कर 1000 रुपए प्रति मी. टन करने और प्राकृतिक गैस पर 50 रुपए से बढ़ा कर 300 रुपए प्रति हजार घन मीटर करने का प्रस्ताव है। पहली मार्च, 1987 से क्रूड तेल पर उपकर की प्रभावी दर को 300 रुपए से बढ़ा कर 600 रुपए प्रति मीट्रिक टन करने का प्रस्ताव है। इन प्रस्तावों से सीमा-शुल्कों के रूप में 800 करोड़ रुपए और उपकर के रूप में 900 करोड़ रुपए की प्राप्ति होने की सम्भावना है तथा कर-भिन्न प्राप्तियों में इतनी ही कमी हो जाएगी। इन वृद्धियों का बोझ पूर्णतः पूल खाते द्वारा वहन किया जाएगा और इनसे उपभोक्ता द्वारा भ्रदा की जाने वाली कीमतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

137. उपर्युक्त प्रस्तावों के अलावा, मैंने उत्पाद-शुल्कों और सीमा-शुल्कों की दरों में परिवर्तन करने के लिए वित्त विधेयक में कुछ संशोधनों का प्रस्ताव किया है। ये संशोधन केवल समर्थकारी उपबन्ध हैं और राजस्व की दृष्टि से इनका कोई महत्व नहीं है। इसके अतिरिक्त मौजूदा, अधिमूचनाओं, उत्पाद-शुल्क नियमों में संशोधन करने के कई प्रस्ताव हैं, जिनका केवल प्रक्रियात्मक महत्व है। सदन के समय की वृत्त करने की दृष्टि से, उनका उल्लेख करने का मेरा विचार नहीं है। सहायक सीमा-शुल्क और विशेष उत्पाद-शुल्क के उद्ग्रहण को जारी रखने के लिए भी वित्त विधेयक में उपबन्ध किए जा रहे हैं।

138. सीमा-शुल्कों और उत्पाद-शुल्कों में 1 मार्च, 1987 से प्रभावी होने वाले परिवर्तनों को लागू करने वाली अधिमूचनाओं की प्रतियां यथा समय इस सदन के पटल पर रखी जाएंगी।

139. सीमा-शुल्कों और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्कों के सम्बन्ध में मेरे प्रस्तावों से, जिनका उल्लेख ऊपर किया गया है, सीमा-शुल्कों के अन्तर्गत 531.73 करोड़ रुपए और उत्पाद-शुल्कों के अन्तर्गत 431.80 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने की सम्भावना है। सीमा-शुल्कों के सम्बन्ध में कुल मिला कर 464.81 करोड़ रुपए और उत्पाद-शुल्कों के सम्बन्ध में 130.00 करोड़ रुपए की रियायतें और राहतें प्रदान की गई हैं। इस प्रकार, सीमा-शुल्कों से 66.92 करोड़ रुपए और उत्पाद-शुल्कों से 301.80 करोड़ रुपए का निवल अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा। उत्पाद शुल्कों में केन्द्र का हिस्सा 109.48 करोड़ रुपए और राज्यों का हिस्सा 192.32 करोड़ रुपए होगा। 368.72 करोड़ रुपए के कुल निवल अतिरिक्त राजस्व में केन्द्र का हिस्सा 176.40 करोड़ रुपए और राज्यों का हिस्सा 192.32 करोड़ रुपए का होगा।

140. मैंने इससे पहले बताया था कि करों की वर्तमान दरों पर वजट में 6,010 करोड़ रुपए का घाटा रहेगा। प्रस्तावित कर उपायों और राहतों के परिणामस्वरूप, केन्द्र को 322 करोड़ रुपए के निवल अतिरिक्त राजस्व की

प्राप्ति होगी। इससे 5688 करोड़ रुपए का घाटा रह जाएगा जिससे लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। यह चालू वर्ष के घाटे से काफी कम है। जैसा कि पहले बताया गया है, मैंने फैसला किया है कि इसे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। मैंने इस फैसले को क्रियान्वित करने के लिए कार्रवाई प्रारंभ कर दी है।

1.41. अध्यक्ष महोदय, मुझे उन भारी चुनौतियों की जानकारी है, जिनका सामना हमारी अर्थव्यवस्था को करना पड़ रहा है। उनमें से कुछ ऐसी हैं, जो किसी जनतांत्रिक व्यवस्था में आयोजित विकास की प्रक्रिया में अन्तर्निहित होती है। लेकिन कुछ ऐसी हैं, जिनका हमें एक स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण करने की कीमत चुकाने के रूप में सामना करना है। भारत की जनता ने अपनी स्वतंत्रता को बरकरार रखा है और स्वच्छापूर्वक इस भार को स्वीकार किया है। उनका साहसिक प्रयास, उनका बलिदान, और अपने सपनों के भारत का निर्माण करने की अपनी सामर्थ्य के प्रति उनका अटल विश्वास मेरे लिए शक्ति, प्रेरणा और मार्गदर्शन का स्रोत है। आइए, हम सब एक दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ें।

1.42. मैं यह बजट सदन को प्रस्तुत करता हूँ।

के.एस. शास्त्री, अपर सचिव (बजट)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

New Delhi, the 28th February, 1987

NOTIFICATION

U.O. No. F. 15(90)-8(D)/86.—Speech of Shri Rajiv Gandhi, Prime Minister and Minister of Finance on Budget 1987-88 is hereby published.

PART A

Sir,

I rise to present the Budget for the year 1987-88.

2. Twenty nine years ago, presenting the country's budget, Jawaharlal Nehru told this House :

"The times we live in and the problems that our country has to face do not permit a static or complacent approach or any avoidance of the burdens which inevitably accompany an attempt to advance with some speed."

We have to strive with all our strength for our planned development by conserving all our resources, increasing production and trying to ensure progressively a more equitable distribution, and thus to raise the standards of the great mass of our people."

These are our objectives today.

3. When we came into office, we were fortunate in inheriting from Indragiri an economy that was sound. After the devastation of 1979-80, the inflation rate was brought down sharply. The growth rate was stepped up, and the infrastructure restored to health. We have built on these successes and initiated a process of reform in areas requiring urgent attention. This, I believe, we have been able to accomplish in large measure.

4. Our principal objectives are the elimination of poverty and the building of a strong, modern, self-reliant, independent economy. In these two years we have sharpened the focus on poverty alleviation. Direct outlays on anti-poverty programmes were substantially increased in the last Budget. The 20-Point Programme (1986) was announced in August. Taking advantage of high stocks of food, rural employment programmes were expanded. Two million tonnes of cereals were made available in tribal areas at highly subsidised rates. We launched an important scheme to enlarge employment opportunities for the urban poor. I have extensively toured and seen the work being done in the most backward and remote villages of our country. Talking to the people face to face, I know how much more needs to be done. I am also convinced that we are making progress in our struggle against poverty.

5. Agriculture is the bedrock of our economy. Growth in this sector is also crucial for the removal of poverty. Our farmers, farm technologists and scientists have turned India from a net-importer of foodgrains living at the margin of survival to self-sufficiency. We are proud of them. We congratulate them.

6. We have reinforced the policies that have proved so successful. We are committed to providing remunerative prices, and increased availability of water, power, seeds, fertilizers and credit to our farmers. Foodgrain production will exceed 150 million tonnes despite a poor monsoon. We have increased incentives to our farmers to reduce our dependence on imports of sugar and edible oils. They have responded magnificently.

7. I am, however, concerned about the situation of agricultural labour. They are subject to exploitation. Government will appoint a National Commission on Rural Labour. It will look into the working conditions of this vulnerable section of our society and the implementation of social legislation for their protection.

8. Industry is forging ahead. Major initiatives for modernising industry and stimulating industrial investment were taken in the Sixth Plan. Our strategy in the Seventh Plan is to build on these initiatives to strengthen industrial performance. We are encouraging economies of scale in production, induction of modern technology and greater competition to increase production, reduce costs and improve quality. We have enhanced the incentives for small scale units. There is clear evidence now that these policies are having the expected impact on the economy.

9. Our industrial base has widened. New industries have developed. The small scale sector has expanded rapidly. A large number of new jobs has been created. In the three years beginning 1984-85, the growth rate in industry is expected to exceed 8 per cent per annum on average this has not happened in the last twenty years.

10. We have given high priority to the important task of tax reform. Our tax laws and rules had become complex. There was widespread evasion. Reform was vital. Our reform of the fiscal system, undertaken in the past two years, has been thoroughgoing. We have made tax rates and the tax structure reasonable. We have simplified laws and procedures. We have enforced these laws vigorously without fear or favour. This has helped the honest tax payer, and yielded more revenue than ever.

11. The public sector is the core of our industrial economy. I am also convinced that our public sector enterprises can be made as efficient as any in the world. I am glad to say that the infrastructure industries in the public sector are showing distinctly better performance. There has been a significant improvement in productivity in coal, power and railways. The improvement in thermal power generation is particularly striking. The plant load factor in the current year is the highest since 1976-77. The improvement in the functioning of infrastructure has been brought about by a change in the management culture, and better performance on the shop floor.

12. Government will further improve the working of public sector enterprises. We will enhance their autonomy, and make them accountable for results. Government will bring before Parliament a White Paper on the public sector.

13. As a nation, we have good reason to be satisfied with our economic performance. During a period when growth rates in many developing countries have declined sharply, we have been able to accelerate growth and increase per capita incomes. We have avoided debt problems, and have kept inflation under control. Our food stocks and foreign exchange reserves are comfortable. These are important strengths. But we cannot afford to be complacent. The world environment, both political and economic, continues to be unfavourable. There are also important domestic problems that demand our attention.

14. The rapid growth in Government expenditure is exerting mounting pressures on our fiscal balance. In the recent period, we have been compelled to increase defence expenditure. We shall spare no effort nor shrink from any sacrifice where our national security is concerned. At the same time, there are pressing requirements for development. Any slackness in critical investments now will cost us heavily in the future. It is a social imperative to spend on programmes which directly benefit the poor and to provide food subsidy. We have had additional commitments arising out of implementation of the Pay Commission's Report. Higher relief and grants had to be provided to several States severely affected by drought and flood.

15. Even so, some hard choices have to be made to keep our expenditure within our means. Government is determined to make them. The situation requires a thoroughgoing review of our expenditure policy. Mere scratching the surface will not help. Ad hoc and across the board cuts of the past, while providing temporary relief, have not yielded enduring results. There is no room for waste, ostentation or unproductive expenditure. We have to pull together and work harder than ever before to realise national goals.

16. We have a good record in price management. However, it will be a mistake to take too complacent view of the price situation. The demand and supply balance in a developing economy is always delicate. Any external or internal disturbance can create difficulties. It is essential, therefore, to keep a careful watch on the price situation.

17. The balance of payments has been under pressure. We had anticipated this and initiated a range of measures to curb the growth of imports and increase exports. These have yielded results. Exports increased by 17 per cent while imports increased by only about 2 per cent in the first nine months of the current year. The trade deficit is lower than last year by Rs. 1,000 crores. But there is much more to be done. Part of the improvement is due to the fall in oil prices and we cannot count on this. Government will remain fully vigilant on the external front.

18. The results of policies initiated in the last two years show that our direction is correct. I propose to use this year's Budget to provide a new thrust in selected areas which will strengthen the economy and further our Seventh Plan objectives. First among these is education.

19. The New Education Policy has been adopted by Parliament after extensive discussions. It has been evolved from a national consensus. It is a powerful weapon to fight poverty. It gives to the socially and economically weaker sections the means to realise equality of opportunity guaranteed by our Constitution. It will help us preserve our heritage and release the creative energy of our youth. It will bind together people speaking different languages, professing different faiths and belonging to diverse cultural traditions that are part of the composite culture of India. It aims at excellence in all fields—science, technology, the arts, humanities and philosophic thought.

20. To give a good start to the new Policy, I have allocated as much as Rs. 800 crores for education as compared with Rs. 352 crores in 1986-87. This massive increase is a measure of our resolve to bring about an educational transformation in our country.

21. State Governments have the primary responsibility for education. These resources will supplement the efforts of State Governments.

22. The momentum of anti-poverty programmes will be maintained. In 1985-86, one million tonnes of foodgrains was provided to States as grant for extending the coverage of the National Rural Employment Programme (NREP) and the Rural Landless

Employment Guarantee Programme (RLEGP), resulting in the creation of 62 million mandays of additional employment. In 1986-87, the additional allocation was increased to two million tonnes, leading to additional employment of 128 million mandays. I propose to continue the Programme of allocating additional foodgrains for employment.

23. The Integrated Rural Development Programme will be strengthened further. This year, more than 3.2 million families are likely to benefit. In the coming year, an outlay of Rs. 310 crores is being provided. Combined with matching allocations of States and credits from the banking sector, the total flow of funds under this Programme will be 4 to 5 times greater than this allocation. Total Plan outlay for the Department of Rural Development will exceed Rs. 2,000 crores in 1987-88. This compares with the total Sixth Plan expenditure of about Rs. 3,600 crores.

24. Housing is high on our list of priorities. It is a basic need. It also generates employment. We propose to launch a comprehensive programme for housing development, particularly housing for economically weaker sections.

25. The Central Government has again earmarked Rs. 125 crores in 1987-88 for the Indira Awaas Yojana. Under this scheme, one million houses will be built during the Seventh Plan period for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. We have decided that State Governments would be free to use the amounts allocated to them under this Programme as seed capital for launching Indira Awaas Yojana Societies for housing loans for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes.

26. A new financial structure will be created to provide funds for housing. At the apex level, a new national housing bank will be set up by the Reserve Bank of India with an equity capital of Rs. 100 crores. This bank will promote housing institutions at both local and regional levels. The Reserve Bank will be announcing the details separately.

27. The National Commission on Urbanisation, in its Interim Report, has suggested several changes in the laws affecting housing, including the Urban Land (Ceiling and Regulation) Act, 1976. This important social legislation aimed at using surplus lands in urban areas for the common good. However, the results achieved have been disappointing. Although 10 years have passed, less than one half of one per cent of the land declared surplus has actually been used for construction. Meanwhile, scarcity of land has pushed up rents and speculative profits in urban areas. The worst sufferers have been the poor. This is not acceptable. I have asked the Ministry of Urban Development to work out suitable legislative proposals taking into account the recommendations of the Commission, and place these before the House for consideration.

28. The Commission has also recommended certain changes in the Rent Control Acts which would give protection to the economically weaker sections, while

also providing sufficient incentive for new constructions. These changes should, over time, bring down rents by improving the availability of housing. The report of the Commission will be commended to State Governments.

29. Later, in my speech, I shall be announcing certain incentives for income tax payers in respect of housing loans taken from specified institutions.

30. In the last two years, Government has taken a number of measures for workers' welfare. These include legislative changes to protect workers' dues, introduction of a new stock option scheme for workers, increase in eligibility limit for bonus payments, increase in the rate of DA for public sector employees, tax concession for investment of workers' housing, increase in the interest rate on workers' Provident Funds and removal of ceiling of house rent allowance for exemption from income-tax. As a further step, I propose to make certain legislative changes in the Income-tax Act to protect the dues of workers by way of Provident Fund, ESI and gratuity.

31. We have achieved remarkable success in mobilising small savings. An expert group, appointed by Government last year, has pointed out certain problems with the present scheme of tax incentives on personal savings. An important lacuna is that fiscal concessions are currently available for gross savings, with no penalty for dissaving. It has, therefore, recommended shifting to a system which gives incentives for net savings.

32. I propose to introduce a new savings scheme based on the net saving principle. To avoid any transitional problems, this scheme will be, for the present, in addition to the existing tax concessions available under Section 80C of the Income-tax Act for National Savings Certificates and other instruments. Under the new scheme, 50 per cent of deposits upto a maximum of Rs. 20,000 will be eligible for deduction. However, in the year of withdrawal, 50 per cent of the amount withdrawn will be added to the taxable income. Receipts under the scheme will be shareable with States. The full details of the new savings scheme, which will be introduced in the next financial year, are being announced separately.

33. The capital markets in India have shown tremendous growth in the last few years. Approvals for capital issues have exceeded Rs. 5,000 crores in 1986-87. They were only about Rs. 500 crores in 1980-81. For a healthy growth of capital markets, investors' rights must be fully protected. Trading malpractices must be prevented. Government have decided to set up a separate Board for the regulation and orderly functioning of Stock Exchanges and the securities industry.

34. Last year, the UTI had set up a Mutual Fund for investment in equity to attract small investors. In order to widen their choice, the State Bank of India will set up a similar Mutual Fund. I shall also be announcing certain measures later which should contribute to the development of capital markets.

35. I have referred to the acceleration in industrial growth. Government's main thrust is to modernise

India's industrial structure. Efficiency and productivity have to be increased. Existing technology has to be upgraded. New technology has to be absorbed and further developed indigenously. Costs must be reduced. All these objectives can only be realised in a medium term time frame.

36. Government have been carrying out an intensive review of individual industries. New policy measures have been announced in respect of several important industries, such as, textiles, jute, sugar, drugs, electronics and software. We have also set up the Textile Modernisation Fund and the Jute Modernisation Fund. These will facilitate modernisation of these traditional industries which provide substantial employment. Another special development fund is being set up for jute. This will benefit growers and workers and promote diversification and research and development.

37. Government will continue to undertake systematic reviews of the total policy framework for selected industries, and take necessary steps to stimulate growth and modernisation.

38. The capital goods industry is central to our efforts for achieving self reliance. It needs immediate attention. I propose to introduce a package of measures to further accelerate the growth of this industry. First, import duty rates for machinery, including general project imports, are being adjusted. Second, in order to reduce costs of domestic manufacture in certain critical sectors, such as power, heavy equipment and textile machinery, cost of certain special types of imported steel is being reduced. I will have more to say on these proposals later.

39. Third, a special programme of technological upgradation for selected capital goods industries will be launched by financial institutions for the three year period upto the end of this Plan. This will cover in the first instance electrical machinery, including power equipment and electric motors, foundaries and machine tools. The objective of this programme will be to induct the latest technology in these sectors improve indigenous R and D facilities for constant upgradation, and reduce costs. The details will be announced separately by the Industrial Development Bank of India.

40. Industries linked to agriculture have a special role in our development. They provide markets for agricultural produce and generate higher incomes for our farmers. I have already referred to the measures taken for modernisation of two of the most important agro-based industries namely jute and textiles. Last years budget had provided important tax incentives for use of certain indigenous oils in vanaspati. I shall be announcing certain proposals to encourage the food processing industries. This will benefit the farmer and the consumers. There are other proposals to benefit cotton and wool.

41. In the past year, Government have taken a number of measures to support export industries. New schemes of cash compensatory support and customs duty drawback have been introduced. Import duties on capital equipment for selected export industries have been reduced. Interest rates have been lowered.

Specified raw materials are being provided at international prices. Fiscal incentives have also been extended. Export are now doing better. In this Budget, I shall be proposing some further measures for increasing export production.

42. Mr. Speaker, Sir, these and other budget proposals will strength the productive forces in our society. The fundamental assumption of the Seventh Plan, as indeed of all our Five Year Plans, is that growth and development are the real antidotes to poverty. Direct measures for alleviation of poverty are indispensable in our society. However, such measures can be sustained only by rapid development. This was the messages that Jawaharlal Nehru gave to the country while introducing the Second Five Year Plan in this House:

"We have, therefore, to lay great stress on equality, on the removal of disparities, and it has to be remembered always that socialism is not the spreading out of poverty. The essential thing is that there must be wealth and production...."

43. We can grow faster only if we use modern technology. This is the only way to deal effectively with the problems of unemployment and poverty. Those wise men who decry the use of modern technology in the name of social justice would do well to listen to Panditji, who in the course of the same speech, said,

"Do not imagine that minus technological progress we are going to deal with the problem of unemployment.....If India is to advance, India must advance in science and technology, and India must use the latest techniques, always keeping in view, no doubt, that in doing so, the intervening period, which always occurs, must not cause unhappiness or misery."

44. This then is our basic strategy—a framework of sustained growth on the basis of rapid modernisation of India's agriculture and industry. I am committed to planning for socialism in India, socialism which fits in with our genius but nevertheless socialism in its basic meaning of removing disparities and providing equality of opportunity. This is the yardstick by which I want to judge all policies and programmes.

45. Let me now turn to The Revised Estimates for 1986-87 and Budget Estimates for 1987-88.

REVISED ESTIMATES 1986-87

46. Budget Estimates 1986-87 provided for a total expenditure of Rs. 52,883 crores. The expenditure in the current year is likely to exceed the original estimate by Rs. 7,445 crores owing to a number of post-budget developments.

47. I do not propose to take the time of the House by going into details as they have been explained in the Budget documents. I shall only refer to certain major items.

48. Non Plan expenditure is expected to be higher by Rs. 5,508 crores including expenditure arising

from the recommendations of the Fourth Pay Commission. To reduce the cost of carrying the buffer stock, the Food Corporation of India is being provided loans of Rs. 1,200 crores on soft terms. This will replace equivalent bank financing. For reasons well known to the House, we have increased defence expenditure by Rs. 1,466 crores. Interest payments will be higher by Rs. 800 crores.

49. Plan expenditure is likely to be Rs. 1,937 crores higher than the original estimates. Budgetary support for the Central Plan is expected to increase from Rs. 13,617 crores to Rs. 14,792 crores. The increase of Rs. 1,175 crores is mainly in Telecommunications, Railways, Petroleum, Mines, Textiles and Atomic Energy sectors. Central assistance for State and Union Territory Plans will be Rs. 762 crores more mainly because of additional Rs. 510 crores of advance Plan assistance to States affected by natural calamities. Taking Plan and Non Plan together, natural calamities assistance to States will be Rs. 640 crores higher than the Budget Estimate of Rs. 150 crores.

50. Coming to receipts, net tax revenue is likely to increase by Rs. 1,564 crores compared with the Budget Estimate of Rs. 22,643 crores. This is a large increase, made possible by vigorous implementation of our tax laws. Non tax revenue and capital receipts including the contributions from the oil sector are estimated at Rs. 27,836 crores against the Budget Estimate of Rs. 26,537 crores. The total receipts are placed at Rs. 52,043 crores and the total expenditure at Rs. 60,328 crores. Inclusive of Rs. 1,200 crores on account of replacement of bank credit for buffer stock by Government loans, the current year is expected to end with Budgetary Deficit of Rs. 8,285 crores.

51. The deficit is high and I do not like it. I have decided that the deficit in the Budget Estimates for 1987-88 shall not be exceeded. Some supplementary demands are unavoidable; I am instructing the Ministries and other Central Government organisations to ensure that additional demands are offset by equivalent savings or through measures to raise more resources. We will review the financial performance of public sector units to ensure that targets for internal resource generation are met. I am constituting a Cabinet Committee on Expenditure to monitor the implementation of these measures.

52. The overall economic situation is good. Our foodstocks and foreign exchange reserves are quite satisfactory. We have been able to keep the overall price situation under control through judicious demand and supply management. Along with expenditure control, we will continue to take anticipatory action to reduce excess liquidity and increase supply of sensitive commodities, particularly foodgrains, sugar and edible oils.

53. Following the report of the Committee on the working of the monetary system in consultation with the Reserve Bank of India, it has been decided that henceforth the Budget documents should show the

budgetary deficit as well as the net change in the Reserve Bank of India credit to Central Government. The latter presents a more accurate measure of the monetary impact of the Government's fiscal operations. According to the present information, it is estimated that the change in the net Reserve Bank of India credit to Central Government in 1986-87 will be Rs. 7,250 crores, which is lower than the budgetary deficit.

BUDGET ESTIMATES 1987-88

54. For 1987-88, in the present situation, I have given the highest priority to maintaining the tempo of the Plan. I have provided an outlay of Rs. 24,622 crores for the Central Plan of 1987-88, of which Rs. 14,923 crores will be provided as budgetary support. With this order of outlay, in the first three years of the Plan, we would have fulfilled about 63 per cent of the Seventh Plan outlay. This is a record.

55. However, we now have to make greater efforts to achieve more for every rupee of investment that we make. Achievement of physical targets is far more important than just spending the money. Government must be more cost effective. The cost of delivery of our programmes must be reduced.

56. The Government has, therefore, given a high priority to implementation of projects in time, avoidance of time and cost over-runs in projects, and the use of innovative methods and new technologies. A monitoring system has been set up for projects under implementation.

57. Revised accounting classification to bring about one to one correspondence between heads of accounts and heads of development used for Plan purposes is being introduced from 1-4-1987 in consultation with the Comptroller and Auditor General of India. This will strengthen the planning process and help better monitoring. Equally important is obtaining timely feed-back from grass root levels regarding implementation of programmes and flow of benefits therefrom.

58. In the Central Plan, a high priority has been given to programmes which have an impact on alleviation of poverty in the rural areas. As I mentioned earlier, particular emphasis has been given to education, the NREP, the IRDP, the RLEGP, rural water supply, and the use of food stocks for creation of additional employment opportunities in the rural areas.

59. Agricultural development has a major impact in alleviating poverty. In the Central Plan, the accent in the agricultural sector continues to be on increasing productivity by increasing the area under high yielding and improved varieties, accelerated transfer of new technology, increasing crop intensity, diversifying the cropping pattern and control of pests and diseases. Some of the important programmes under implementation are : Special Rice Production Programme, National Oil-seeds Project, National Watershed Development Programme and National Pulses Development Project. These projects are designed to solve specific agricultural problems, and are already making an impact in our rural areas.

60. Irrigation and fertilizers are two major components of programmes for increasing agricultural productivity. In irrigation a high priority is being given to the completion of on-going projects and for bridging the gap between irrigation potential and its utilisation. Fertilizer production in the current year will increase to nearly 7 million tonnes from about 5.7 million tonnes last year. The fertilizer plant at Paradeep has commenced production during the year. In the next year, the fertilizer plants at Vijaipur and Aonla—each with a capacity of 7.2 lakh tonnes of urea are expected to be commissioned.

61. In terms of financial outlays, infrastructure sectors, namely, energy, transport and communications will account for more than 54 per cent of the total Central Plan. In 1987-88, taking the Centre and States together, we will be commissioning 4880 MW of additional power capacity. In coal, the output per man-shift has improved by 11 per cent. The target for coal production in 1987-88 is 183.5 million tonnes as against 165 million tonnes in 1985-86.

62. In the Sixth Plan, we were able to increase our crude oil production nearly three-fold. In the current Plan, production is likely to show a slower increase and it is necessary to accelerate investment in exploration and development of new oil fields. The total outlay for the petroleum sector as a whole is Rs. 3,265 crores next year.

63. In order to save the time of the House, I have mentioned only a few of the highlights of the Central Plan for 1987-88. In several other areas, such as, women and child development, health and family welfare, youth affairs and sports, art and culture, science and technology, environment, social forestry and information and broadcasting, this Government has taken several new initiatives to make the Plan more meaningful to our people. These programmes are being strengthened. Necessary provisions have also been made for industrial projects, including those in heavy industry, steel and mines.

64. I am also happy to inform the House that the total Plan outlay of States and Union Territories for 1987-88 has been fixed at Rs. 19,537 crores representing an increase of 17 per cent over the current year. We have taken care of the requirements of Arunachal Pradesh and Mizoram on being elevated to Statehood. A provision of Rs. 8,754 crores has been made next year for Central assistance for State and Union Territory Plans as against Rs. 8,140 crores in the current year's Revised Estimates.

65. The Budget Estimate for defence is Rs. 12,512 crores in 1987-88. This has naturally cast a heavy burden on our budgetary resources, but the House will agree with me that no compromise is possible where country's defence is concerned. The strength and morale of our Armed Forces are high. On behalf of this House, I assure our Jawans of the unstinted support of the entire nation.

66. Interest payments next year are estimated at Rs. 10,650 crores against Rs. 9,550 crores in the current year. Food and fertilizer subsidies including

arrears, are placed at Rs. 3,910 crores as against Rs. 3,893 crores in the current year. Next year's Budget includes a lump provision of Rs. 500 crores to cover likely increases in additional dearness allowance to Government employees and also the increases in pensionary charges arising out of the recommendations of the Fourth Pay Commission. This Government—ever sensitive to the difficulties of pensioners—has decided to increase the minimum pension and minimum family pension to Rs. 375 per month. This will benefit nearly six lakh pensioners.

67. The total Non Plan expenditure in 1987-88 is estimated at Rs. 39,266 crores. Tax revenue next year net of States' share is estimated at Rs. 25,689 crores against Rs. 24,207 crores in the current year. Non tax revenue and capital receipts are placed at Rs. 31,243 crores against Rs. 27,836 crores in the current year. The total receipts at existing rates of taxation thus amount to Rs. 56,932 crores against the total expenditure of Rs. 62,942 crores, leaving a gap of Rs. 6,010 crores.

68. I shall now turn to my tax proposals.

PART B

69. In the 1985-86 Budget, we initiated a process of major tax reform. The broad direction and strategy for this reform was set out in the Long Term Fiscal Policy (LTFP). We will be introducing a detailed Amendment Bill on Direct Taxes separately in the Budget Session. This Bill will implement wide ranging changes aimed at simplification and rationalisation.

70. The basic thrust of my few Direct Tax proposals is to provide incentives for savings to promote investment and to support housing. I propose to strengthen some welfare measures. I have also included some measures to enhance revenue.

71. I do not propose any changes in the rate structure for Personal and Corporate Taxes. This is in line with the Long Term Fiscal Policy.

72. In order to conserve foreign exchange and to raise revenue, I propose to levy a modest tax of 15 per cent on foreign exchange released in India for foreign travel. Foreign exchange released for medical treatment and education abroad will be excluded. This tax will be applicable for travel from a date to be notified. The revenue yielded from this measure is expected to be Rs. 60 crores.

73. Those who can afford to patronize high class hotels should also be afforded the further pleasure of contributing to the national exchequer. A separate legislation will be brought forward for levy of a tax on expenditure in expensive hotels. This tax, to be levied at 10 per cent of expenditure, will not apply to payments made in foreign exchange. It will become effective after passage of the necessary legislation.

74. I have already mentioned the decision to introduce a new National Savings Scheme based on net savings. Necessary legislative changes are being included in the Finance Bill.

75. I propose to provide a fiscal incentive for channelising savings into the housing sector. Repayment of loans and payments made to the extent of Rs. 10,000 in a year towards the cost of any new residential property will qualify for deduction on the same lines as life insurance premia or contribution to provident fund under Section 80C of the Income-tax Act. This exemption will be within the existing limit of Rs. 40,000.

76. Capital gains arising from the sale of a residential house are exempted in case such gains are utilised for acquiring another house. This was hitherto applicable only to individuals. It is now being extended to Hindu Undivided Families.

77. I understand that for the purpose of taxation of income from houses, our tax laws make a distinction between a real owner who is not a legal owner and a legal owner who is not a real owner. Following the well-established revenue tradition, when it comes to taxing, we tax both the real owner who is not a legal owner and the legal owner who is not a real owner. Concessions available to a house owner are, however, given only to a real owner who is also a legal owner. I propose to simplify the law by clarifying that the real owner, even if he is not the legal owner, will pay the tax and avail of the concessions available to the legal owner. I hope this proposal is abundantly clear to the Hon'ble Members.

78. In cases where the compensation for acquisition of a property is enhanced, or where a new residential house is not acquired within the specified time after selling the old house, the completed tax cases for the past years have to be modified to tax the capital gains accrued earlier. Certain procedural changes are being made in the law to remove this complication.

79. Several important changes have been introduced in the corporate tax structure in the last two years. With effect from April, 1987, a liberalised set of depreciation rules is being introduced. Depreciation will be allowed in respect of blocks of assets instead of the present system linked to individual assets. There will be only three rates of depreciation for plant and machinery, namely, 100 per cent, 50 per cent and 33-1/3 per cent. Apart from simplifying assessment, this will enable industry to replace and modernise capital equipment faster.

80. It is only fair and proper that the prosperous should pay at least some tax. The phenomenon of so-called "zero-tax" highly profitable companies deserves attention. In 1983, a new Section 80VVA was inserted in the Act so that all profitable companies pay some tax. This does not seem to have helped and is being withdrawn. I now propose to introduce a provision whereby every company will have to pay a "minimum corporate tax" on the profits declared by it in its own accounts. Under this new provision, a company will pay tax on at least 30 per cent of its book profit. In other words, a domestic widely held company will pay tax of at least 15 per cent of its book profit. This measure will yield a revenue gain of approximately Rs. 75 crores.

1687 GII86-4

81. The capital markets have shown remarkable buoyancy. I propose to make some changes in the Tax Laws which will support healthy development of the capital markets. The existing provision of allowing deduction in respect of investment in equity shares of certain categories of new companies was to be withdrawn with effect from 1st April, 1987. In view of the need to continue support for issues of new companies, I propose to extend this concession for 3 more years. I also propose to reduce the holding period of these shares from 5 years to 3 years.

82. At present shares have to be held for a period of 36 months before capital gains on their transfer qualify for the concessional treatment allowed for long term capital gains. It is proposed to reduce the holding period to 12 months. This will provide greater flexibility to investors and also improve the mobility of capital invested in shares.

83. Concentration of industries in many of our urban areas poses serious problems of congestion, pollution and hazards. In order to encourage industries to shift out of such areas, I propose to exempt capital gains made on the sale of land and buildings in such areas provided these are reinvested in approved relocation schemes.

84. The provisions regarding additional income-tax on undistributed profits of closely held companies have lost their relevance after the reduction in tax rates effected in 1985-86 Budget. These are being deleted. Because of some court decisions, the capital gains on transfer of goodwill of a concern or transfer of assets from a firm to a partner and vice-versa escape the tax net. Such gains will be explicitly taxable.

85. A tax holiday to newly established undertakings in Free Trade Zones has been provided. It is being clarified that this will also extend to units which develop software as also those which assemble or process components for exports.

86. A tax concession is available to the Indian companies earning income from a foreign Government or a foreign enterprise for imparting technical knowhow. This tax concession will now be available only if the foreign exchange earned is repatriated to India. It is also being clarified that an Indian resident cannot be treated as a foreign enterprise for this purpose.

87. It is proposed to exclude computers and machines for transmission and reception of messages from the list given in the Eleventh Schedule of the Income-tax Act as these industries are no longer non-priority.

88. At present Indian citizens earning remuneration in foreign currency for services rendered abroad are allowed 50 per cent exemption under Section 80 RRA of the Income-tax Act subject to certain conditions. This is being further liberalised. The exemption will now be allowed to the extent of 50 per cent of the remuneration, or 75 per cent of the remuneration repatriated in convertible foreign exchange, whichever is higher.

89. In order to improve coverage and prevent tax evasion, it is proposed that tax at specified rates should be deducted at source in respect of all payments

beyond certain prescribed amounts of fees for professional and technical services, royalty, rent, commission or brokerage and payments for goods supplied to Government, etc. This will apply to payments made by all persons, excepting individuals and Hindu Undivided Families.

90. Let me now come to measures for the welfare of workers, members of armed forces and the handicapped. There are a number of cases where the employers do not credit their own contributions nor those of the employees to the Provident Fund and the State Insurance Fund. It is also unfortunate that a separate fund is not being kept by some employers in respect of gratuity of workers. To prevent this anti-labour practice, we propose to penalise such delinquent employers by providing that the contributions of the employees to these funds will be taxed as the income of the employer and allowed as a deduction only when they are made over to the separate accounts relating to these funds within the time allowed under the statute.

91. Any compensation received by a workman at the time of his retrenchment is exempt from tax. Similar exemption is being extended to payments made under voluntary retirement schemes for public sector employees.

92. Regimental Funds or non-public Funds are utilised for purposes such as providing assistance to widows of armed personnel killed in action, as also to disabled soldiers. The contributions will enjoy similar tax concessions as other funds of national importance like the National Defence Fund.

93. I am increasing the special deduction allowed to the physically handicapped persons and the totally blind from Rs. 10,000 to Rs. 15,000.

94. There are other procedural proposals in the area of Direct Taxes including those to ensure better functioning of the Settlement Commission which are in the Bill.

95. For the Members of Parliament, I propose to introduce a general exemption in respect of Constituency Allowance without reference to any monetary ceiling.

96. The above proposals will give a net revenue gain of Rs. 145 crores.

97. Let me now turn to Indirect Taxes. The tariff regime for capital goods will be restructured and rationalised. I propose to extend MODVAT to most of the remaining areas. Excise and Customs duties for certain industries are being adjusted to stimulate growth. There is a package of reliefs for the common man.

98. As I mentioned earlier, the capital goods industry needs special support.

99. At present, there are two tariff rates for import of machinery: 101 per cent for import of general machinery and a concessional rate of 55 per cent when machinery is imported for a new project. The low duty rates for project imports have provided a strong encouragement for unnecessary imports. The differential between the general rate and the project

rate also discriminates against modernisation of existing units, and favours sickness. These anomalies must be corrected.

100. I propose to equalise the two rates at 85 per cent. The rate of duty applicable for components will be 15 per cent below the applicable tariff rate.

101. At present, fertilizers, power and electronics are allowed concessional import duty on their capital goods imports. These rates are being adjusted upwards. The duty on import of equipment for the electronics industry is being raised from 25 per cent to 30 per cent and for fertilizer plants, it is being increased from zero per cent to 15 per cent. In the case of power, plants of above 50 MW capacity will continue to be imported at 25 per cent. Plants of 50 MW and below will pay a higher duty of 35 per cent.

102. Further concessions are needed to encourage upgradation of technology in specified capital goods sectors.

- (i) At present, domestic capital goods manufacturers have to pay very high import duties on import of special steels. The duty rate is being reduced to 85 per cent on steels such as boilers-pressure-vessels-quality plates, sheets or coils, turbine blade flats and stainless steel plates.
- (ii) The textile machinery industry will be allowed supply of imported stainless steel at concessional duty of 55 per cent instead of the prescribed rate of 245 per cent at present.
- (iii) In order to encourage modernisation of foundries, import duty on specified capital goods is being reduced from 101 per cent to 55 per cent.
- (iv) Caustic soda plants presently based on mercury-cell technology should be encouraged to convert into membrane-cell technology. The new technology saves energy and reduces pollution. Specified equipment required for this conversion will be allowed imports at concessional duty of 35 per cent instead of the present 101 per cent.

103. The MODVAT introduced in the 1986-87 Budget was a major innovation. We covered 38 chapters of the Excise Tariff last year. I now propose to extend MODVAT to all the remaining chapters except those relating to textiles, tobacco and the petroleum sectors. MODVAT will now be extended to cover food products, mineral products, leather and travel goods, footwear, paper and paper-board, wood and cork products, asbestos cement products and precious metals.

104. Last year, in order to ensure revenue neutrality, the introduction of MODVAT was accompanied by an increase in the duty on the final product to balance the set-off being given of the duty paid on inputs. This year, keeping in view the nature of products, the duty on the final product is not being increased except in a few items. This will reduce the effective duty on a large number of items.

105. In the case of food products, for example, the total number of items covered by MODVAT will be over 100. The duty increase for revenue neutrality is being done only in case of cheese, malt preparations and aerated soft drink. The effective rate of taxation on other food products, such as biscuits, skimmed milk powder, butter, jams and jellies, and confectionery will be significantly reduced. Farmers and horticulturists are benefited by the expansion of the market of value-added food products.

106. Some increase in the final duty is necessary in five of the items which were covered last year where we have found that set-off given last year was very much larger than initially estimated. These are zinc-oxide, adhesives based on synthetic resin, organic surface-active agents, electric motors and primary batteries.

107. A number of important procedural changes are also being introduced to simplify the operation of MODVAT. Some of the concessions are :

- (1) Refund in cash of input duty credit if the final product is exported by the manufacturer in certain circumstances.
- (2) Availability of credit of duties in respect of inputs lying in stock.
- (3) Adjustment of input duty credit if additional duty is demanded from input manufacturers in case of change in classification of inputs.
- (4) Receipt of inputs directly by the job-workers will be permitted for all items under the MODVAT scheme.

108. With these measures, we will have successfully eliminated the cascading effect of excise duty and given a measure of excise relief.

109. Our comprehensive policy package has made electronics one of the fastest-growing industries. It has generated substantial employment. I propose to make certain changes which will strengthen the basic design of the existing policy.

110. For computers, the following reliefs and rationalisations are being carried out :—

- (i) Import duty on electronic sub-assemblies is being reduced from 308 per cent to 150 per cent.
- (ii) The list of peripherals is being enlarged and a uniform rate of import duty of 60 per cent is being specified.
- (iii) Import duty on specified data-communication equipment is being reduced from 140 per cent to 100 per cent. Duty on mechanical parts of data-communication equipment is being reduced from 140 per cent to 55 per cent.
- (iv) The present notification regarding exemption of import duty on computer peripherals for Research Institutes is being extended by 3 years.

(v) Duty on computer systems imported under OGL is being reduced from 150 per cent to 140 per cent (basic and auxiliary).

(vi) Import duty on specified electronic parts of computers is being increased from 25 per cent to 75 per cent in order to give appropriate protection for indigenous production. The import duty on mechanical parts of computer peripherals is also being increased from 5 per cent to 75 per cent; and this is being extended to mechanical parts of CNC system.

111. The Indian computer industry achieved a turnover of Rs. 225 crores last year. It has passed its infancy and is healthy and vigorous. Now that the industry has arrived, can the tax-collector be far behind? It is proposed to levy an excise duty of 10 per cent on computers and peripherals. With MODVAT, the effective incidence of duty will be much lower.

112. The research and development base of the electronics industry is crucial for its long-term success. I, therefore, propose to reduce the duty on specified equipments required for R&D from 140 per cent to 55 per cent.

113. We must also encourage domestic production of capital goods required for the electronics industry. At present, mechanical components required for manufacture of such capital goods attract a duty of 140 per cent. I propose to reduce this duty to 45 per cent in the case of components required for nearly 300 specified machines.

114. In the field of general electronics, a concessional duty structure of 30 per cent, 45 per cent and 75 per cent is allowed for imports of raw materials, piece-parts and components, respectively. We are expanding the coverage of this concessional duty structure by adding some more items.

115. I propose to abolish the excise duty on the production of poly-silicon in all forms as a measure of support for the domestic industry. The customs duty for the import of silicon, solar cells and photo-voltaic systems is being fixed at 30 per cent, 45 per cent and 75 per cent, respectively. I propose to increase the duty on the import of poly-silicon to 75 per cent for electronics industry in the interest of domestic production.

116. Production of television sets has increased rapidly in line with targets. A thriving and competitive industry has been set up. I propose to make two changes :

- (i) As an anti-avoidance measure, it is proposed to impose an excise duty for countervailing duty of Rs. 150 on black and white tubes meant for sets of size above 36 cms. and to impose an excise duty or countervailing duty of Rs. 600 on all colour television tubes. Under MODVAT, this input duty would be fully rebated to duty-paying manufacturers with no additional duty burden on the consumer. It will, however, help to check unlicensed production.

- (ii) The excise duty on colour television sets exceeding 36 cms. size is presently Rs. 1,500 irrespective of the value of the set. I propose to increase the duty on costlier sets to Rs. 1,750 per set. This will apply to sets cleared at assessable value higher than Rs. 5,000 which corresponds to a retail price of about Rs. 7,500. The excise duty for sets cleared at assessable value of Rs. 5,000 or below will remain at Rs. 1,500. The costlier sets can bear the extra duty.

117. These proposals relating to the electronics industry will involve a net loss of revenue of Rs. 19.33 crores. There will be a revenue gain of Rs. 40 crores in excise duty and a loss of Rs. 59.30 crores in customs duty.

118. Important developments have taken place in the automobile industry in the past few years. New technology has been introduced, production has increased and indigenisation is taking place. Government have been reviewing these and other developments and will be announcing a comprehensive policy. For the present, I have the following tax proposals encourage indigenisation.

- (i) At present, a concessional rate of customs duty of 50 per cent is allowed for imported sub-components required for the manufacture of components for fuel-efficient trucks, cars, and two-wheelers. I propose to enlarge the list of components eligible for concessional import of sub-components this will encourage indigenisation.
- (ii) Excise duty on fuel-efficient motor vehicles with engine capacity not exceeding 1000 c.c. is proposed to be increased from 20 per cent to 25 per cent. This sector can bear the additional duty and it will still benefit from a lower rate than the rest of the industry.
- (iii) For handicapped individuals, I propose to provide for total exemption from customs duty in respect of automatic transmission and other special equipment to be fitted into fuel-efficient cars of engine capacity not exceeding 1000 c.c.
- (iv) The rate of duty on import of spares for meeting the after-sales or warranty of fuel-efficient motor vehicles is being increased from 50 per cent to 75 per cent.
- (v) Excise duty on tractors will now be fixed on engine capacity instead of Power-Take off-Horse-Power. This is an anti-avoidance measure with no revenue implication.

119. Plastics are widely used by the common man. They also have a tremendous potential for use in farms and factories. Our plastic prices are high. Government propose to initiate measures to reduce costs in this important area.

120. I propose to reduce the basic customs duty on PVC resin (general-purpose suspension-grade) from Rs. 10,500 per metric tonne to Rs. 7,500 per metric

tonne. These resins are used in the manufacture of cheap footwear, pipes for agricultural application and as insulation for wires and cables.

121. I also propose to reduce the basic customs duty on Low-Density-Polyethylene (LDPE) from 100 per cent to 75 per cent. LDPE is used as a base for production of a wide range of packaging materials. LDPE film has a big potential use in the lining of canals and farms and field-channels.

122. The excise duty on products of regenerated cellulose, which includes the cheap packaging material-cellophane, is being reduced from 40 per cent to 20 per cent. Excise duty is being similarly reduced on cellulose acetate moulding granules which is used for spectacle-frames, umbrella handles, tooth-brushes and on sodium carboxy-methyl cellulose which is used in oil-drilling, textiles processing and detergents.

123. Excise duty on certain varieties of industrial plastics i.e. acrylic and vinyl resin emulsions is being reduced from 40 per cent to 20 per cent.

124. Over the past year, we have taken a number of steps to strengthen our export performance through fiscal and other means. I propose to give the following additional incentives.

- (a) For the gem and jewellery industry, customs duty on 46 additional items of tools, machinery etc. is being reduced to 35 per cent.
- (b) For the marine products industry, 3 additional items will be allowed concessional import duty of 40 per cent (basic and auxiliary).
- (c) For the leather industry--
 - (i) 31 additional items of machinery required for leather industry will be allowed concessional duty of 25 per cent.
 - (ii) polyurethane film/foil used for improving finished leather will have lower countervailing duty of 40 per cent.
 - (iii) polyurethane leather required for the manufacture of football for exports will be exempted from duty.
- (d) The import duty on tyre moulds required for export production is being reduced to 25 per cent.
- (e) Export duty on mica products is being abolished except for mica waste and scrap.
- (f) Import duty on flax and ramie fibres is being reduced from 80 per cent to 40 per cent.

125. I also propose to make some adjustments which will further benefit the common man :-

- (1) In August 1985, Government introduced a scheme of fiscal relief for the manufacture of inexpensive blended fabrics-Sulabh fabrics. Under this scheme, NTC mills are supplied raw material free of excise duty for the manufacture of suitings of value upto Rs. 45 per metre and shirting of value upto Rs. 20 per metre. This scheme has made a

good start. It is now proposed to have a similar scheme for manufacture of Saubhagya sarees. This will make available good-quality sarees at reasonable prices.

- (2) At present, footwear of Rs. 45 per pair is exempt from excise duty. I propose to raise the limit to Rs. 60 per pair of assessable value which corresponds to footwear retailing at about Rs. 100 per pair. To offset the revenue loss, excise on footwear exceeding this assessable value is being increased to 15 per cent for leather footwear and 20 per cent on footwear of synthetic resins.
- (3) Janata soaps of value not exceeding Rs. 10,000 per metric tonne bear a lower rate of excise duty of 5 per cent. I propose to raise the value limit to Rs. 12,000 per metric tonne. This should reduce the cost of cheaper toilet and laundry soaps. Soaps of value between Rs. 12,000 per metric tonne and Rs. 25,000 per metric tonne will continue to pay duty at 15 per cent but expensive soaps, whose value exceeds Rs. 25,000 per metric tonne will be charged 25 per cent.
- (4) Complete exemption from excise duty is available in respect of shoddy woollen fabrics of assessable value not exceeding Rs. 40 per sq. mtr. I propose to raise the limit to Rs. 60 per sq. mtr. Shoddy blankets are already fully exempt from excise duty.
- (5) Excise duty on fluorescent tubes is being reduced to the specific rate of Rs. 2 per tube. The other fittings and parts of such tubes will also pay reduced excise duty at the rate of 10 per cent.
- (6) I also propose to exempt, from excise duty, bio-gas appliances such as stoves, hot plates and lights. This would encourage greater use of bio-gas.
- (7) Specified life-saving equipment is presently fully exempt from customs duty but import of spares needed for such equipment attracts duty. This is an unnecessary burden on our hospitals and clinics. I propose full exemption also for spares and accessories of such life-saving equipments.
- (8) Items like note-books, letter-pads, blotting pads, registers, account books, file covers are being exempted from excise duty altogether.

126. I have two proposals for cotton textiles :—

- (i) I propose to liberalise the Small-Scale Scheme for hand-processed fabrics by increasing the full exemption limit from 36 lakh sq. mtrs. to 50 lakhs sq. mtrs., in case of hand-processed cotton fabrics.
- (ii) The excise duty structure on cotton fabrics in the power-processing sector is being rationalised. Specific rates of excise duty are being provided in respect of fabrics of

value upto Rs. 25 per sq. mtr. This will involve a revenue loss of Rs. 15 crores.

127. I propose to remove excise duty on wool tops altogether. However, I propose to increase the customs duty on raw wool, woollen rags and wool waste from 20 per cent to 30 per cent and reduce the customs duty on synthetic rags from 80 per cent to 30 per cent. Excise duty on polyester-wool-blended yarn is also proposed to be reduced from Rs. 30 per kg. to Rs. 15 per kg. This will benefit cheaper varieties of woollen textiles.

128. The present rates of duty on viscose staples fibre and viscose filament yarn have not been revised for a number of years. As a revenue measure, I propose to increase the excise duty on viscose staple fibre from Rs. 5 per kg. to Rs. 7 per kg. Similarly, excise duty on viscose filament yarn is also being increased by about 12.5 per cent of the existing rates. These measures together will give us an additional revenue of Rs. 24 crores.

129. As the House is aware, there is a scheme which has replaced sales-tax on sugar, tobacco and textiles by an Additional Excise Duty (AED). The proceeds of AED go entirely to the State Governments. The AED is required to be raised to reach the agreed level of tax incidence. The rate of duty on costlier fabrics of assessable value exceeding Rs. 100 per sq. mtr. is being increased to 20 per cent. The total revenue gain of AED will be Rs. 40 crores and will be passed on wholly to State Governments.

130. I now propose to deal with some other industries which require relief :—

- (1) As a result of recent policies, cement production has grown rapidly benefiting the consumer and converting a sellers' market into a buyers' market. The newer units in the industry need some support in view of their high capital costs. I, therefore, propose a rebate of excise duty at the rate of Rs. 50 per metric tonne in respect of portland cement manufactured by units commencing production of such cement on or after 1-4-1986. This rebate will be available for a period of three years from 1-3-1987. The levy quota in respect of such units is also being reduced from the existing 30 per cent to 15 per cent. The excise concession will be available only to those units whose aggregate production is not less than 30 per cent of the licensed capacity.

- (2) I propose to allow imports of specified machinery for improvement in productivity and quality of solvent-extracted oils and oilmeals at concessional duty rate of 55 per cent. Last year, we introduced a system of rebate in excise duties for vanaspati and soap linked to larger use of minor oils. This has had the desired effect and production of rice-bran oil as well as its use in vanaspati and soap have increased considerably. The rebate scheme is being continued this year.

There are some procedural changes and the ad valorem duty on vanaspati is being changed to a specific duty.

- (3) Better food-packaging and food-processing can contribute greatly to raise the income of our farmers. I have already made some proposals in plastics which will help. I further propose to reduce the import duty on specified items of machinery and aseptic packaging from 101 per cent to 50 per cent.
- (4) I propose to exempt 36 more drug intermediates used either exclusively or predominantly in the manufacture of drugs from additional duty of customs. In addition, I propose to lower the customs duty to 70 per cent on two specified drug intermediates required for the manufacture of pyrazinamide, an anti-TB drug.
- (5) Customs duty on specified raw materials for refractories is being reduced.
- (6) It is proposed to reduce excise duty on unwrought aluminium of CG-grade from 13 per cent to 11 per cent.
- (7) I propose to reduce excise duty on feature films, including dubbed feature films by about 10 per cent of the existing duty leviable.
- (8) Denatured-ethyl-alcohol of specified strength, when imported for use exclusively for industrial purposes, is being exempted from customs duty in excess of 60 per cent ad valorem.
- (9) It is proposed to merge the two existing SSI schemes for the refrigeration and air-conditioning appliances and machinery industry into one and to liberalise it. Full exemption from excise duty will now be available for clearance upto Rs. 5 lakhs. Thereafter, 50 per cent of the excise duty leviable will be applicable for clearance between Rs. 5 lakhs and Rs. 15 lakhs. Subsequently, the unit will pay the normal duty but eligibility limit for retaining exemption and concessions for the unit will be Rs. 40 lakhs.
- (10) I propose to extend the concessional rate of customs duty of 20 per cent in respect of HBI (Hot Briquetted Iron) sponge iron and melting scrap of steel available to electric arc furnace units to induction furnace units also.
- (11) Customs duty on fluorspar (natural calcium fluoride) used for manufacture of aluminium

fluoride is being reduced from 110 per cent to 75 per cent.

- (12) I also propose to reduce customs duty to 25 per cent for plant and equipment needed for manufacture of family-planning apparatus and appliances and also of equipment using non-conventional energy sources. The same low-duty rate is being applied for certain specified sophisticated fire-fighting equipment for fire-fighting services administered by Central|State|U.T. Governments and local bodies.

131. In looking for more revenue, I have to fall back on the ever dependable and reliable friend of Finance Ministers and the certified enemy of Health Ministers. Lately, I am told, the friendly relationship has been marred by disputes and litigation. I now propose to restore amity between the two by moving over to a new and more rational system of levying excise duties.

132. The existing scheme of excise duty on cigarettes is based on the printed retail price. I propose to move over to an entirely new scheme of specific excise duty based on the length of the cigarette. This is the system prevalent in many countries. It ensures unambiguous determination of the excise duty, avoiding all problems of determining either assessable value or sale value.

133. It is proposed that for non-filter cigarettes of size upto 70mm, the excise duty would be Rs. 150 per 1000 cigarettes. In case of filter cigarettes, the excise duty will be in four slabs namely, upto 70mm, over 70 upto 75 mm, over 75 upto 85mm, over 85 upto 100mm. The rates of duty per 1000 filter cigarettes in these slabs will be Rs. 200, Rs. 300, Rs. 400 and Rs. 600, respectively. The tariff rate for cigarettes is Rs 700 and, therefore, non-filter cigarettes beyond 70mm length and filter cigarettes beyond 100mm length will pay the tariff rate.

134. This scheme will be a major simplification and rationalisation measure. Incidentally, it will also yield additional revenue to Government of Rs. 200 crores.

135. I will now mention some other measures largely of rationalisation :—

- (1) Denudation of our forests is causing serious damage to our environment. The tax structure must also make a contribution towards preservation of our forest wealth. With this objective in view, we have rationalised the duty structure on wood products. I propose to levy a uniform rate of excise duty of 20

per cent on wood products based on waste wood such as particle-board, insulation and hard-boards and fibre-boards. A higher rate of 30 per cent will be levied on all plywoods made from prime timber. I invite suggestions from Members and other conservationists and I am prepared to take further measures which would implement this policy objective.

- (2) Excise duty on snuff and chewing tobacco or products containing chewing tobacco is being imposed at the rate of 25 per cent.
- (3) A large number of exemption, notifications in customs have the effect of lowering the rate of duty below 25 per cent for many items. In order to prevent invoicing mal-practices, rates of duty should not be below 25 per cent except in very special circumstances. Accordingly, duty rates are being raised to 25 per cent for 7 items. In a few other cases, the duty rates have been reviewed and increased.
- (4) The concessional rate of 25 per cent (basic) in respect of soda ash will continue until 31st March, 1988.
- (5) The 70 per cent concessional duty on 13 specified parts of mechanical and quartz analogue wrist watches will continue for another year with certain modifications. The rate of duty is being enhanced to 100 per cent for three specified parts. The concessional rate in respect of certain other parts of wrist watches is being withdrawn altogether.
- (6) The excise duty on aerated soft drink is being increased by 20 paise per bottle and in the case of soda, by 15 paise per bottle. Soda and soft drinks in packagings other than bottles will have a duty of 60 per cent and 57 per cent, respectively. MODVAT benefits will now be available to these items. Hence, the effective incidence will be considerably lower.
- (7) Processed foods of various types are charged 15 per cent excise duty. The list of such processed and relatively expensive packaged foods is being extended to noodles, spaghetti, macaroni, vermicelli, flakes of cereals, ready-to-cook food-mixes, etc. put up for sale in unit containers.
- (8) Basic customs duty on unwrought aluminium is proposed to be raised from 20 per cent ad valorem to 35 per cent plus the normal additional duty. This is necessitated by the upward revision of domestic aluminium

prices to equate the landed cost of imported metal with the statutory price per tonne.

- (9) I propose to raise the excise duty on steel ingots made by mini-steel plants from Rs. 315 per tonne to Rs. 365 per tonne so as to equate the duty with steel ingots produced by the integrated steel plants. Even at the revised rate, the ad valorem incidence of excise duty will be lower than on the steel produced by integrated plants because of substantial MODVAT credit and higher prices.

136. I am also taking this opportunity to bring the surplus of the Oil Pool Account into the tax-net. This will have no effect on consumer prices. This surplus presently accrues to Government as non-tax receipts. I now propose to raise the customs duty on imported crude petroleum by Rs. 500 per tonne. I also propose to increase the ceiling limits upto which excise duty by way of cess for the development of oil industry may be levied on crude oil and natural gas produced in India. The limits are proposed to be raised from Rs. 300 per tonne to Rs. 1000 per tonne on crude oil and from Rs. 50 to Rs. 300 per thousand cubic metres on natural gas. The effective rate of cess on crude oil is proposed to be raised from 1st March, 1987 from Rs. 300 to Rs. 600 per tonne. The proposals are expected to yield Rs. 800 crores by way of customs duty and Rs. 900 crores by way of cess with an equivalent reduction in non-tax receipts. These increases will be absorbed fully by the Pool Account and will not affect prices paid by the consumer in any way.

137. Apart from the above proposals, I have proposed certain amendments in the Finance Bill seeking to effect changes in the excise and customs tariffs. These amendments are merely enabling provisions and have no revenue significance. Besides, there are several proposals for amendments in existing notification, excise rules which have merely procedural significance. In order to save the time of the House, I do not propose to recount them. Provision in the Finance Bill is also being made for continuation of the levy of auxiliary duty of customs and Special Excise duty.

138. Copies of notifications giving effect to the changes in customs and excise duties effective from 1st March, 1987, will be laid on the table of the House in due course.

139. My proposals in respect of Customs and Central Excise duties outlined above are likely to yield additional revenue of Rs. 531.73 crores from Customs duties and Rs. 431.80 crores from Excise duties. The concessions and reliefs aggregate Rs. 464.81 crores on the Customs side and Rs. 130.00 crores on the Excise side. The net additional revenue from Customs duties thus would be Rs. 66.92 crores

and that from Excise duties, Rs. 301.80 crores. In Excise duties, the Centre's share would be Rs. 109.48 crores and that of States, Rs. 192.32 crores. Out of the total net additional yield of Rs. 368.72 crores, Centre's share would be Rs. 176.40 crores and that of the States, Rs. 192.32 crores.

140. I had earlier mentioned that the Budget deficit at the existing rates of taxes would be Rs. 6,010 crores. The proposed tax measures, taken together with reliefs, are estimated to yield net additional revenue of Rs. 322 crores to the Centre. This will leave an uncovered deficit of Rs. 5,688 crores. This is significantly lower than the deficit for the current year. As mentioned earlier, I have decided that this shall not be exceeded. I have set in motion measures to implement this decision.

141. Mr. Speaker, Sir, I am conscious of the enormous challenges that confront our economy. Some are inherent in the process of planned development in a democracy. But some are in the nature of a price that we have to pay for pursuing an independent foreign policy. The people of India have asserted their independence and willingly accepted these burdens. Their heroic exertions, their sacrifices, and their unshakable confidence in their capacity to build the India of their dreams are a source of strength, inspiration and direction to me. Let us move forward with determination.

142. I commend the Budget to the House.

K. S. SASTRY, Addl. Secy. (Budget)